मासिक पत्रिका

जून 2026, ₹ 10.00

दीप कमल

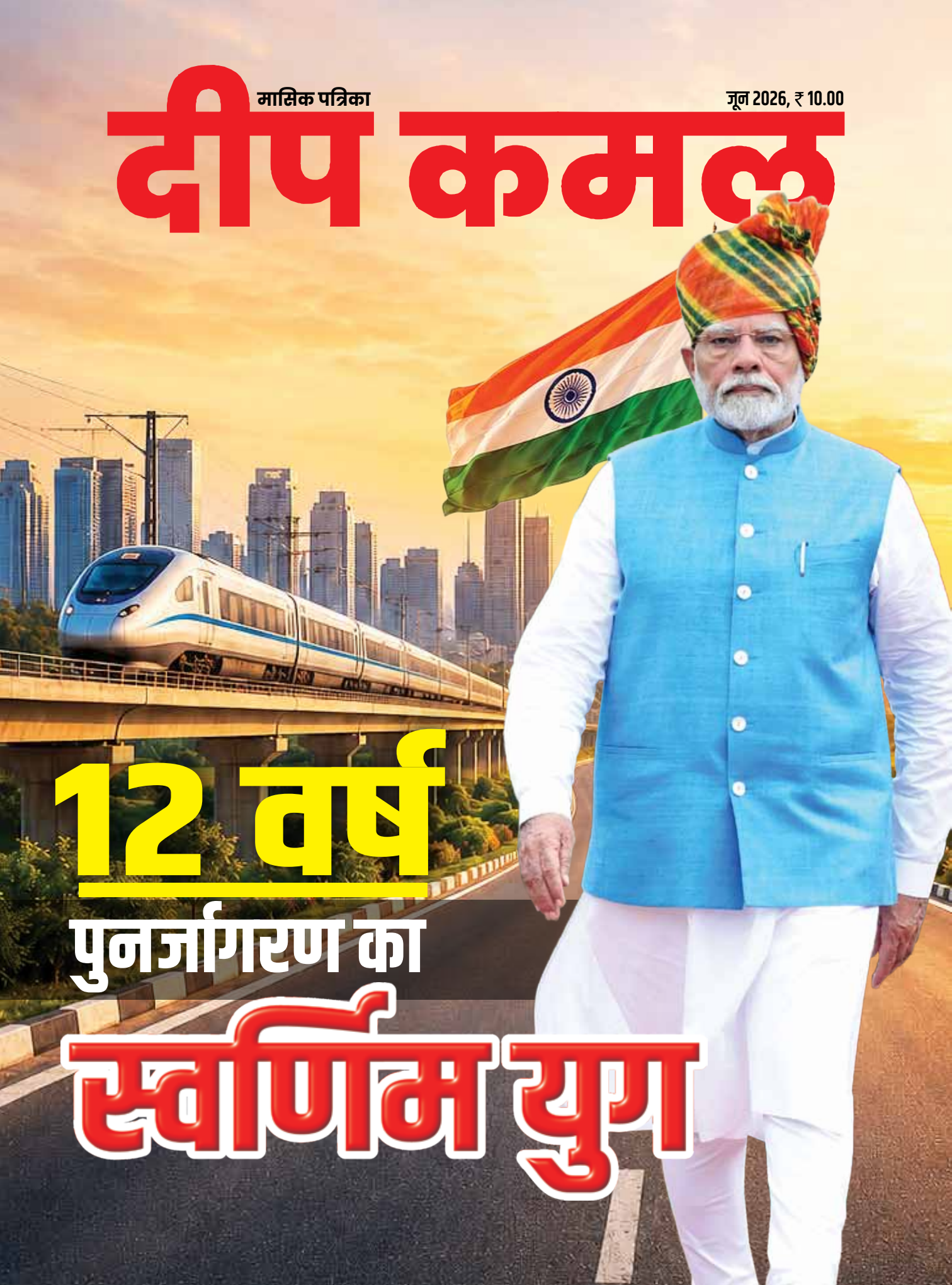

12 वर्ष

पुनर्जागरण का

स्वर्णिम युग

प्रदेश पदाधिकारी बैठक

दीप कमल

वर्ष-22, अंक-6, जून 2026

संपादक
पंकज कुमार झा

प्रबंध संपादक
हेमंत पाणिग्रही

मुद्रक एवं प्रकाशक
किरण देव द्वारा, भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ के लिए, विश्व परिवार से मुद्रित एवं कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, बोरियाकला, रायपुर से प्रकाशित।

पत्रिका दीप कमल के इस अंक का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए कृपया QR कोड स्केन करें।

www.deepkamal.online

स्वत्वाधिकारी
भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़

mydeepkamal@gmail.com
0771-2233500, 2233511
92016-33511

सोशल मीडिया से

मैं जवाहर लाल नेहरू बोल रहा हूं...

भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय गणराज्य के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का कीर्तिमान बनाने के अवसर पर इस संपादकीय में कल्पना की गई है कि पं. नेहरू इतिहास के झरोखे में बैठकर इस प्रकार मोदीजी के योगदान की व्याख्या कर रहे हैं।

इतिहास बड़ा ही निष्ठुर होता है। वह नीर-क्षीर विवेकी भी होता है, अगर उसके दूध में सायास पानी न मिला दिया गया हो। इतिहास के कालखंड में सात-आठ दशक इतना होते भी नहीं कि उसमें पीढ़ियों का फासला हो। इतिहास के लिए तो स्वतंत्रता का कालखंड भी मानो कल की ही बात है। इतिहास के ऐसे ही झरोखे में आराम करते हुए मैं जवाहरलाल नेहरू आजकल नए भारत की खोज कर रहा हूं। इतिहास की समाप्ति हो गई है जैसा कि फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा था। हालांकि भारतीय मान्यता की बात करें तो इतिहास के स्वयं का इतिहास इतना छोटा प्रतीत होता है कि इसके जनक माने जाने वाले हेरोडॉटस भी कल आए जैसा ही लगते हैं। ऐसे में 70-80 वर्ष तो खैर कुछ होता ही नहीं।

ऐसे ही इतिहास के शिकंजे में बैठा मैं सोच रहा हूं कि आखिर नया भारत कैसा है? क्या यह वही है जैसा नियति से वादा या करार हमने किया था? क्या वह पूरा हुआ? निस्संदेह मैं यह कह सकता हूं कि भारत के नए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी ने वे सारे वादे पूरे किए हैं जो हमें या मेरे परिवार से आए लोगों को दशकों पहले कर लेना चाहिए था। आज यह बहस छिड़ी है कि मैं अर्थात् नेहरू श्रेष्ठ थे या आज मोदीजी? मेरा स्पष्ट मानना है, अनेक ऐसी चीजें और तथ्य हैं, जिससे मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि मोदी भारत के प्रधानमंत्रियों में श्रेष्ठ हैं। हमारे द्वारा सायास या अनायास छोड़ दिए गए सभी कार्यों को मोदीजी ने देश के लिए संपादित करते हुए भारत को वह बनाया है जैसा बापू का सपना था। जैसा सपना मेरे समान हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, जैसा देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले मनीषियों ने देखा था। जैसा स्वप्न अपने स्वाभाविक श्रेय से वंचित कर दिए गए ऐसे गुमनाम-अनाम सपूतों ने देखते हुए फिरंगी गोलियों के आगे अपनी छाती अड़ा दिया था।

ऐसे तमाम मामले हैं जिन्हें इतिहास के झरोखे से मैं देखने की कोशिश करता हूं तो ऐसा लगता है कि काश कोई ऐसी टाइम मशीन होती जिसके द्वारा मैं 80 वर्ष पीछे जाकर वह सब कर आता जैसा आज नरेंद्र दामोदरदास मोदी कर रहे हैं। मैं आज जब इतिहास के कंटकयुक्त आसान पर बैठकर वर्तमान का मूल्यांकन करने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरे पास पश्चाताप के दर्जनों अवसर सामने दिख रहे हैं। सभी का प्रायश्चित यही समझ आ रहा है कि मैं वास्तव में यह स्वीकार कर लूं कि लगभग हर मामले में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रेष्ठ हैं।

अब क्योंकि बिना किसी दुराग्रह के नीर-क्षीर विवेक के साथ आत्मचिंतन करने का समय है, तो मुझे यह मानने में कोई गुरेज नहीं है कि श्री नरेंद्र मोदीजी महानतम हैं। ऐसी महानता उन्होंने अपने कर्मयोग से अर्जित किया है न कि उन पर यह महानता थोप दी गई है। हमने अपनी तात्कालिक राजनीति के कारण भले बड़े-बड़े कर्मयोगियों को श्रेय नहीं दिया लेकिन मेरे उन तमाम अपराधों का एक ही प्रायश्चित है कि बड़े मन से आज मैं स्वीकार कर लूं कि गांव और देहात में बसे भारत की समझ मेरे जैसों को कम रही है। हमने भारत को किताबों और उद्धरणों में पाश्चात्य दृष्टि के अनुसार समझा था, जबकि पढ़ा गया भारत, भोगा गया भारत उससे बिल्कुल अलग है और था भी। वैसा तो यह भारत कदापि नहीं है जैसा मैंने पढ़कर संकलित करने की कोशिश की थी या जिसकी खोज कर लेने का मुगालता मैंने पाल लिया था।

मैं मूलतः कश्मीरी हूं, किन्तु मैंने कश्मीर के दर्द को भी उस तरह महसूस नहीं किया जैसा एक भारतीय के रूप में हमें करना चाहिए था। अनुच्छेद 370 और '35 अ' जैसी चीजें केवल तुष्टीकरण के कारण करना मेरी भयावह भूल थी, अपनी जिद में मैंने मेरे मंत्रिमंडलीय सहयोगी और मां भारती के विद्वान सपूत डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी की भी नहीं सुनी, यहां तक कि उनकी संदेहास्पद मृत्यु तक के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि तब के भारत में मैंने 'तुष्टीकरण' को अघोषित भारतीय नीति बना दिया था।

आज जब मैं, अपने कहे जाने वाले दल की स्थिति देखता हूं तो पश्चाताप इसलिए भी होता है कि मैंने कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में समाप्त कर 'लोक सेवक संघ' बना देने की बापू की बात नहीं मानी। अपनी हत्या से पहले वाली रात ही महात्मा ने कांग्रेस की समाप्ति का मसौदा तैयार कर लिया था, सुबह ही हो गई हत्या के अजीब संयोग के लिए भी इतिहास का कटघरा आज प्रचलित मान्यताओं के उलट सोचने पर विवश कर रहा है। अब समय के पहिये को पीछे लौटाना संभव नहीं है, मेरे उत्तराधिकारियों ने जिस तरह तुष्टीकरण के विष-बीज को जहरीले पेड़ के रूप में परिणत कर दिया और स्वतंत्र भारत ने जैसा-जैसा दंश झेला, उसे सोचकर मेरी पीड़ा का पारावार नहीं रहता, मैं अब यह महसूस करता हूं कि वंशवादी राजनीति को मुझे प्रश्रय नहीं देना चाहिए था।

आज इतिहास के शिकंजे में जकड़ा हुआ स्वयं को मैं उस अश्वत्थामा की मानिंद पाता हूं जिसके मस्तक से सतत रिसते मवाद उसके कृत्यों की याद दिलाते रहते हैं। हमारा राजनीतिक भारत भी तो तब पांडव के बच्चों जैसा अबोध ही था, जिसे पाल-पोसकर बड़ा किया जाना था। हमने कश्मीर विषय पर तब पैदा हुए आक्रोश को शांत करने यह जुमला कह दिया था कि अनुच्छेद 370 घिसते-घिसते घिस जाएगा, हालांकि इस बात का भरोसा मुझे रत्तीमात्र भी नहीं था कि सच में इसे घिस देना संभव होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में इस विषय को ले जाते हुए अधिक बेहतर तरीके से सोच नहीं पाने की अपनी अक्षमता मैं स्वीकार करता हूं। कहीं न कहीं हजारों कश्मीरी पंडितों की हत्या, उन्हें अकारण ही उनकी भूमि से खदेड़ देने, अपने ही देश में शरणार्थी बनकर नारकीय जीवन जीने को विवश करने का दोषी मैं स्वयं को भी पाता हूं। मोदी महान इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने उस अनुच्छेद को सचमुच घिस डाला। इसीलिए भी मैं यह कहने पर विवश हूं कि मोदी महानतम हैं, उन्होंने मेरे द्वारा आधे-अधूरे मन के साथ किए गए नियति के तमाम करारों को मनोयोग से पूरा किया है। उन्होंने मेरे मंत्रिमंडलीय सहयोगी रहे डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी की स्मृति को महानतम श्रद्धांजलि दी है।

प्रश्न केवल कश्मीर का ही नहीं है, मेरे गुट-निरपेक्षता के सिद्धांत को सकारात्मक स्वरूप मोदीजी ने दिया है। आज हम सभी गुटों से समान दूरी रख देश में अलग-थलग पड़ जाने के स्थान पर सभी देशों से समान निकटता की मोदी नीति के कारण अधिक

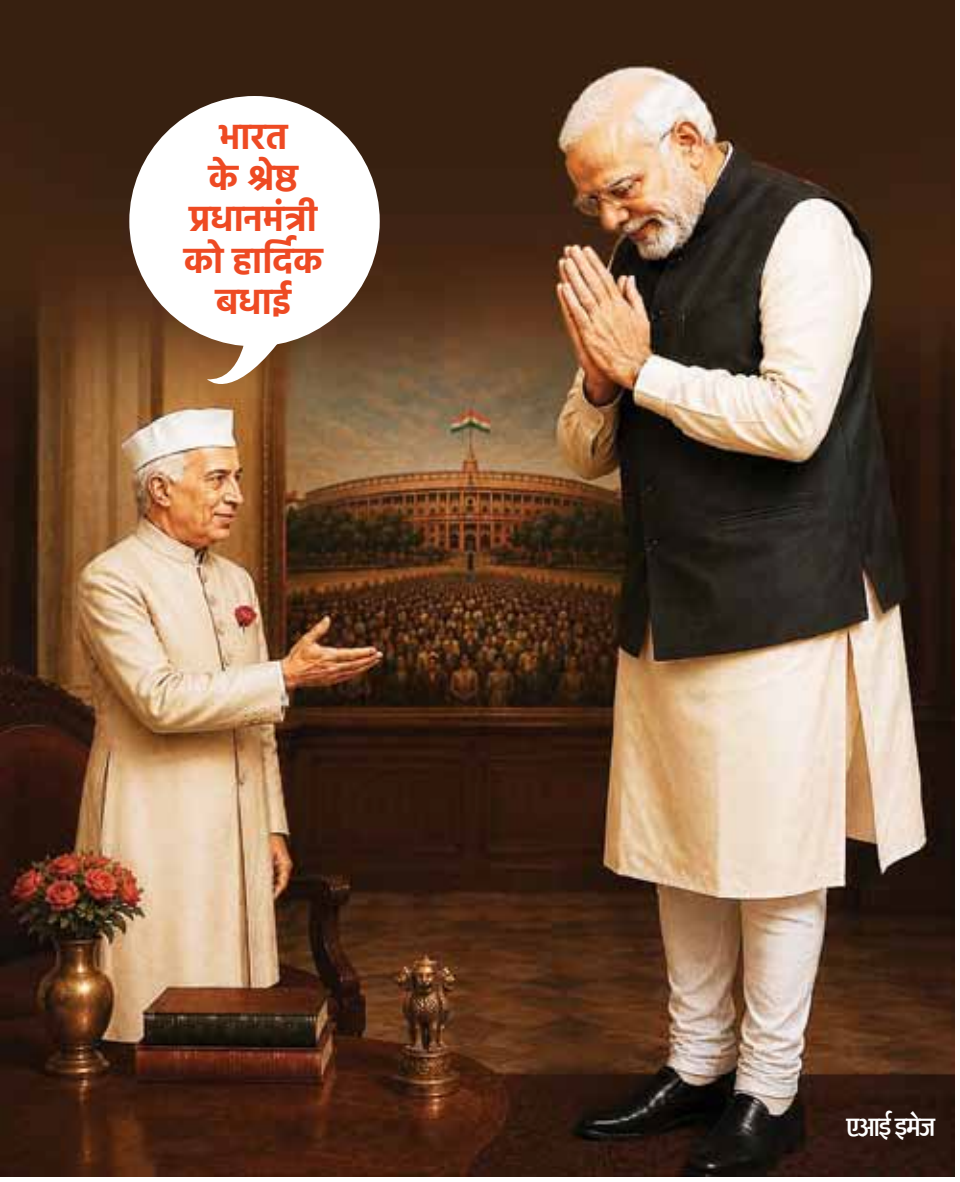

सुरक्षित हैं, इसके लिए भी मोदी की महानता स्वीकार करने में मुझे रत्तीभर का संकोच नहीं है। भारत का विभाजन, सरदार पटेल को उचित स्थान नहीं दिया जाना, डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी को सोमनाथ पुनरुद्धार के अवसर पर वहां जाने से रोकने की कोशिश, प्रथम राष्ट्रपति द्वारा फिर भी वहां चले जाने का बदला उनके अंतिम संस्कार तक में नहीं जाने, उन्हें सीलन भरे कमरे में पटना के सदाकत आश्रम में रहने को विवश करने, राष्ट्रपति राधाकृष्णन जी तक को जाने से मना करने आदि का अब अवश्य अफसोस हो रहा है मुझे। साथ ही इस बात का संतोष है मुझे कि सोमनाथ हमले के हजार वर्ष पूरे होने पर आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के नाते मोदीजी द्वारा सोमनाथ का वैभव पुनर्स्थापित किया गया है।

इसी तरह एकांगी मित्रता का मेरा पूर्वाग्रह, हिन्दी-चीनी भाई-भाई का नारा, सुरक्षा परिषद में भी भारत के लिए आए स्थायी सदस्यता के अवसर को चीन को सौंप देना, सेना आदि को सुदृढ़ करने में मेरी वैचारिक अनिच्छा का दंश जिस तरह भारत को भोगना पड़ा, जिस तरह चीन की धोखेबाज प्रवृत्ति को समझने में मुझसे भूल हुई, जिस तरह मेरी जिद के कारण देश का इतना बड़ा नुकसान हुआ, उससे मुझे बेतरह शर्मिंदगी है। सियाचिन में तो घास का एक तिनका तक नहीं उगता, मैं विपक्ष को कुचल दूंगा जैसे मेरे बयानों के लिए मैं देश से माफी मांगता हूं। यह देखकर मुझे अब खुशी हो रही है कि मोदीजी के नेतृत्व का सशक्त भारत आज गलवान से लेकर डोकलाम तक उसे मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। हमारे हर किए की भरपाई करने में मोदीजी की भूमिका उन्हें महानतम बनाती है।

मैं जब-जब मेरी बेटी के पोते कहे जाने वाले राहुल गांधी के बचकाना बयानों को देखता हूं, युद्ध की-सी हालत में भी अपने ही देश के सरेंडर हो जाने की घोषणा करते हुए उसे देखता हूं तो लगता है मुझे कि वंशवादी विषवृक्ष खड़ा कर मैंने कितनी बड़ी भूल की है। मुझे ऐसे समय याद आते हैं पुरी के श्रीजगन्नाथ मंदिर का निर्माण करने वाले राजा इंद्रद्युम्न, जिन्होंने यह वरदान मांग लिया था कि वे निर्वंश हो जाएँ ताकि उनके किए का श्रेय जबरन लेने उनके वंशज न आगे आने पाए। अब ध्यान आ रहा है कि महात्मा गांधीजी की भी चिंता यही थी। मेरे अयोग्य और अक्षम वंशजों ने यह साबित भी किया है कि वंशवादी राजनीति आज भारत का कोढ़ है जिसका अधिकतम इलाज मोदीजी कर पा रहे हैं।

अपनी तमाम भूलों का एक ही निष्कर्ष मुझे समझ में अब आता है कि सोने का चम्मच मुंह में रखकर पैदा होने वाले मेरे जैसे लोगों को कभी नेतृत्व के लिए आगे नहीं आना चाहिए। भारत को समझने के लिए भारत जैसा जीवन जीना और अनुभव करना आवश्यक होता है। पहले के विपरीत अब मैं स्वयं को 'एक्सीडेंटल हिन्दू' नहीं मानते हुए यह कामना व्यक्त करता हूं कि सनातन आस्थाओं के अनुसार जब भी मेरा पुनर्जन्म हो तो मैं किसी चायवाले के घर ही जन्म लूं। ऐसा इसलिए ताकि भारत को समझते हुए भारतीय दृष्टि से भारत का निर्माण करने के मोदीजी के विजन का अनुकरण कर सकूं।

कहने को अनेक बातें हैं। माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता, हालांकि नाभा जेल से बाहर आने के लिए अंग्रेजों से मेरे द्वारा माफी मांगा जाना अनुचित था, पर अपने भारत से माफी मांगने में मुझे तनिक भी संकोच अब नहीं है। प्रयागराज और उसके इर्द-गिर्द खेतों में छिड़क दी गई मेरी राख का एक-एक कण आज यह कहने की अनुमति चाहता है कि मोदीजी आप महान श्रेष्ठ हैं, ईश्वर द्वारा भारत को मिला एक अमूल्य उपहार हैं आप।

भारतीय गणतंत्र के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के मेरे रिकार्ड से आगे निकल जाने के लिए मैं महान भारत के महानतम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी को बधाई देता हूं, साथ ही अपने किए उन सभी भूलों के लिए जिनमें से कुछ का ही जिक्र मैं यहां कर पाया हूं, समूचे देश से माफी मांगता हूं।

अशेष शुभकामनाएं और बधाई। |•••

आपका ही जवाहर

पंकज...

@pankaj_media

Email : jay7feb@gmail.com

इस संपादकीय के बारे में अपने विचार आप मेल कर सकते हैं।

सभ्यतागत चेतना के पुनर्जागरण का युग

नितिन नवीन

यदि हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के इतिहास को देखें तो उनकी सफलता के पीछे जो एक मूलमंत्र नजर आता है, वह है उस राष्ट्र का 'सामूहिक स्वप्न'। भारत के संदर्भ में वर्ष 2014 में पहली बार 140 करोड़ की विशाल जनता को सामूहिक चेतना के एक सूत्र में पिरोने का ऐतिहासिक कार्य प्रधानमंत्री मोदी ने किया। देश को पहला ऐसा नेतृत्व मिला है जो एक 'प्रधान सेवक' के भाव से 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के महासंकल्प को लेकर निरंतर आगे बढ़ रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने विश्वास, विकास और जनकल्याण को समर्पित अपने 12 वर्ष पूर्ण किए हैं। 'संकल्प से सिद्धि' का यह गौरवशाली कालखंड भारत के विकास, सुरक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण और वैश्विक प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि का साक्षी रहा है। कांग्रेस देश को अनिश्चितता, भ्रष्टाचार और कमजोर नेतृत्व की विरासत देकर गई थी, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को आत्मविश्वास, सुशासन और विकास की नई पहचान दी है। कांग्रेस के लिए राजनीति का मतलब वर्षों तक परिवार की विरासत को बचाना रहा, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के लिए राजनीति- 'परिवार नहीं राष्ट्र प्रथम' और 'सत्ता नहीं सेवा प्रथम' का मार्ग रही है।

यदि हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के इतिहास को देखें तो उनकी सफलता के पीछे जो एक मूलमंत्र नजर आता है, वह है उस राष्ट्र का 'सामूहिक स्वप्न'। भारत के संदर्भ में वर्ष 2014 में पहली बार 140 करोड़ की विशाल जनता को सामूहिक चेतना के एक सूत्र में पिरोने का ऐतिहासिक कार्य प्रधानमंत्री मोदी ने किया। देश को पहला ऐसा नेतृत्व मिला है जो एक 'प्रधान सेवक' के भाव से 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के महासंकल्प को लेकर निरंतर आगे बढ़ रहा है। 2014 में प्रधानमंत्री ने पहले राष्ट्र को एक 'सामूहिक सोच' दी, फिर जन-विश्वास के बल पर उस सोच को 'सामूहिक संकल्प' में बदला और आज वही संकल्प 'विकसित भारत' के रूप में 'सामूहिक स्वप्न' का रूप ले चुका है।

इस महापरिवर्तन की शुरुआत बुनियादी ढांचे की अभूतपूर्व क्रांति से हुई। 2014 से पहले देश बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहा था। आज जमीनी स्तर पर बदलाव का परिणाम है कि 12 करोड़ से अधिक शौचालय बने, 100 प्रतिशत विद्युतीकरण हुआ, एक्सप्रेस-वे नेटवर्क 7 गुना बढ़ा और एयरपोर्ट्स 74 से 160 से अधिक हो गए। यह कालखंड मानसिक गुलामी से मुक्ति और वास्तविक 'डी-कलोनाइजेशन' का साक्षी है। लोक कल्याण मार्ग, कर्तव्य पथ और सेवा तीर्थ का नामकरण और योग का वैश्विक प्रसार इसका प्रमाण है। एक समय था जब देश के शीर्ष नेतृत्व ने तत्कालीन 54 करोड़ की आबादी को बोझ माना था, पर आज प्रधानमंत्री मानते हैं कि यही 140 करोड़ देशवासी भारत के विकास की गाथा की सबसे मजबूत कड़ी हैं। इसी सोच ने अनुच्छेद 370 को हमेशा के लिए निरस्त किया। आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई गई। कोरोना काल में 220 करोड़ से अधिक मुफ्त वैक्सीन डोज और 'वैक्सीन मैत्री' ने वैश्विक स्तर पर भारत की क्षमता का परिचय दिया।

आज का युवा 'जॉब सीकर' नहीं, बल्कि 'जॉब गिवर' बन रहा है। 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स और 125 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स के साथ भारत मैनपावर से 'मैन्युफैक्चरिंग पावर' की ओर बढ़ रहा है। इसी प्रकार, देश 'वीमेन डेवलपमेंट' से आगे बढ़कर 'वीमेन लेड डेवलपमेंट' का साक्षी बन रहा है, जहां 3 करोड़ से अधिक 'लखपति दीदी' और सुरक्षा बलों में महिला अधिकारियों की 4 गुना वृद्धि नारीशक्ति के स्वावलंबन को दर्शाती है। मोदी सरकार ने मातृशक्ति को सम्मान, सुरक्षा, स्वाभिमान और हिस्सेदारी देने में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।

गरीब कल्याण के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं ने वंचितों के 'विशियस साइकिल' (दुष्चक्र) को 'वर्चुअस साइकिल' (गुणात्मक चक्र) में बदल दिया है, जिससे 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 4 करोड़ पक्के घर, 60 करोड़ नागरिकों को आयुष्मान कवच और पीएम मुद्रा योजना के तहत 40 लाख करोड़ रुपए का कोलेटरल-फ्री लोन इसका आधार बना। डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में, '1 रुपए में से सिर्फ 15 पैसे पहुंचने' के पुराने दौर को समाप्त कर दिए गए। डीबीटी के माध्यम से 51 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजे। जनधन-आधार-मोबाइल

(जैम) ट्रिनिटी और यूपीआई के माध्यम से आज 314 लाख करोड़ का वार्षिक डिजिटल लेनदेन हो रहा है जो वैश्विक स्तर पर 49 प्रतिशत है। प्रकृति के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए भारत ने स्वच्छ भारत अभियान, एक पेड़ मां के नाम और सोलर कैपेसिटी को 2.6 जीडब्ल्यू से 110+ जीडब्ल्यू तक पहुंचाकर ग्रीन अर्थ के संकल्प को सिद्ध किया है।

प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में आज देश के सीमावर्ती क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है। कभी देश के अंतिम गांव कहे जाने वाले ये क्षेत्र आज भारत के प्रथम गांव के रूप में नई पहचान पा चुके हैं। इसके साथ ही आज भारत की सैन्य क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और हमारी सेनाएं अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित हैं। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम और महाकाल महालोक का जीर्णोद्धार हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की उस सभ्यतागत चेतना का पुनर्जागरण है जो विकास भी, विरासत भी के मूलमंत्र को पूरी सार्थकता से साकार कर रहा है।

पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरे देश का सोचने का ट्रेंड भी बदला है। आज नए भारत का मिजाज ऐसा है जहां आंत्रप्रेन्योर (उद्यमी) बनना एक ट्रेंड है, कड़ी मेहनत करना एक ट्रेंड है और वोकल फॉर लोकल से लेकर मेक इन इंडिया को अपनाना हर नागरिक का मूलमंत्र बन चुका है। यह ऐसा दौर है जहां तीव्र विकास के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करना एक ट्रेंड है। आज देश में स्पिरिचुअल टूरिज्म का एक नया उभार दिख रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात, 'नेशन फर्स्ट' के भाव के साथ, एक सामूहिक संकल्प के साथ काम करना देश का ट्रेंड बन चुका है। इन तमाम सकारात्मक बदलावों के पीछे प्रधानमंत्री की भूमिका एक ट्रेंडसेटर की रही है जिन्होंने इनके माध्यम से आज पूरे देश को एकता के एक मजबूत सूत्र में पिरो दिया है। आज भारत न केवल आंतरिक रूप से सशक्त हो रहा है, बल्कि वैश्विक पटल पर भी एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। जब प्रधानमंत्री को विश्व के 32 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त होता है तो यह वास्तव में सनातन भारतीय सोच और 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ का सम्मान है। यही कारण है कि आज विकसित भारत केवल एक नारा नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसे देशवासियों ने अटूट विश्वास और संकल्पित भाव से आत्मसात किया है।

भारत का सामूहिक स्वप्न...

सरकार के ये 12 वर्ष जहां सेवा, सुशासन और जन-आकांक्षाओं की पूर्ति के रहे हैं, वहीं अगले 21 वर्ष विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की यात्रा होंगे। इस अमृतकाल में सभी देशवासी मिलकर एक सशक्त, समृद्ध, सुरक्षित, स्वावलंबी, समर्थ और समरस भारत के सामूहिक स्वप्न' को अवश्य साकार करेंगे।

सेवा, सुशासन और संकल्प के 12 वर्ष

विकसित भारत की यात्रा के हम सब साक्षी

विष्णु देव साय

प्रधानमंत्री जी ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' को केवल नारा नहीं रहने दिया, बल्कि इसे शासन की कार्यसंस्कृति बनाया। जन-धन योजना ने गरीबों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा, आधार और मोबाइल की जैम ट्रिनिटी ने सरकारी योजनाओं को पारदर्शी बनाया और डीबीटी ने लाभ सीधे हितग्राहियों के खाते तक पहुंचाया। इससे भ्रष्टाचार और बिचौलिया व्यवस्था पर प्रभावी रोक लगी। शासन पहली बार सचमुच अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचा।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा के 12 वर्ष पूरे होना उस परिवर्तनकारी कालखंड का प्रतीक है, जिसने देश की दशा और दिशा को बदला है। वर्ष 2014 में देश ने एक ऐसे नेतृत्व पर विश्वास जताया, जिसने शासन को सत्ता का माध्यम नहीं, सेवा का संकल्प माना। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो स्पष्ट दिखाई देता है कि इन 12 वर्षों में भारत ने सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक आत्मविश्वास के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है।

प्रधानमंत्री जी ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' को केवल नारा नहीं रहने दिया, बल्कि इसे शासन की कार्यसंस्कृति बनाया। जन-धन योजना ने गरीबों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा, आधार और मोबाइल की जैम ट्रिनिटी ने सरकारी योजनाओं को पारदर्शी बनाया और डीबीटी ने लाभ सीधे हितग्राहियों के खाते तक पहुंचाया। इससे भ्रष्टाचार और बिचौलिया व्यवस्था पर प्रभावी रोक लगी। शासन पहली बार सचमुच अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचा।

गरीब कल्याण इस दौर की सबसे बड़ी पहचान रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 81 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने करोड़ों गरीब परिवारों को पक्का घर दिया। उज्ज्वला योजना ने माताओं-बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाई। आयुष्मान भारत ने गरीब परिवारों को महंगे इलाज की चिंता से राहत दी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने अन्नदाताओं को सीधी आर्थिक सहायता दी। ये योजनाएं केवल सरकारी घोषणाएं नहीं रहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और विश्वास का आधार बनीं।

इन 12 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने भी नई शक्ति प्राप्त की है। आत्मनिर्भर भारत अभियान ने देश को केवल उपभोक्ता बाजार नहीं रहने दिया, बल्कि उत्पादन, नवाचार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का मजबूत केंद्र बनाने की दिशा दी। मोबाइल निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उत्पादन, सेमीकंडक्टर, फार्मा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में भारत तेजी से आगे बढ़ा है। आज भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में आत्मविश्वास के साथ खड़ा है।

डिजिटल इंडिया ने भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। यूपीआई ने डिजिटल भुगतान को आम आदमी के जीवन का हिस्सा बना दिया है। गांवों तक इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं की पहुंच ने शासन को तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया है। कोविड काल में कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीकाकरण का सफल संचालन भारत की डिजिटल क्षमता का बड़ा उदाहरण रहा। आज भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया के लिए मॉडल बन चुका है।

आधारभूत संरचना के क्षेत्र में भी पिछले 12 वर्ष ऐतिहासिक रहे हैं। आधुनिक राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेस-वे, वंदेभारत ट्रेनें, नए एयरपोर्ट, मेट्रो नेटवर्क, अमृत भारत स्टेशन और बेहतर लॉजिस्टिक्स ने देश की गति बढ़ाई है। सड़क, रेल, हवाई और डिजिटल कनेक्टिविटी ने भारत के उन क्षेत्रों को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ा है जो लंबे समय तक

उपेक्षित रहे थे। यही कनेक्टिविटी विकसित भारत की मजबूत रीढ़ बन रही है।

छत्तीसगढ़ में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में हमें मोदी जी की गारंटी पर जनादेश मिला। महतारी वंदन योजना के तहत पात्र हितग्राही महिलाओं को एक हजार रुपये प्रति माह देकर महिला सशक्तीकरण का नया अध्याय लिखा जा रहा है। पहली ही कैबिनेट में हमारी सरकार ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को मंजूरी देकर अंत्योदय के मंत्र को चरितार्थ किया है। प्रदेश में 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी हो रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। हमने मोदीजी की सारी गारंटियों को पूरा कर राजनीतिक प्रतिबद्धता को ऊंचाई प्रदान की है।

आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई इस कालखंड की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। वर्षों तक देश के अनेक आदिवासी और वनांचल नक्सली हिंसा, भय और पिछड़ेपन के चक्र में फंसे रहे। प्रधानमंत्री जी के साहसिक नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की सफल रणनीति के अनुसार डबल इंजन की सरकार में नक्सलवाद की जड़ों पर निर्णायक प्रहार हुआ। बस्तर, जिसे कभी नक्सल हिंसा के कारण जाना जाता था, आज विकास, विश्वास और बदलाव की नई पहचान बना रहा है। 31 मार्च 2026 तक माओवाद को समाप्त करने का संकल्प सरकार ने पूरा किया। जिन क्षेत्रों में कभी भय था, वहां अब स्कूल, सड़क, स्वास्थ्य सुविधा, मोबाइल कनेक्टिविटी, बैंकिंग सेवा और सरकारी योजनाएं पहुंच रही हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर मोदी सरकार की नीति स्पष्ट रही है,राष्ट्रहित सर्वोपरि और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस। उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक तथा ऑपरेशन सिन्दूर ने दुनिया को यह संदेश दिया कि नया भारत अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करता। सीमा सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा,नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक नीति ने देशवासियों के मन में नया विश्वास पैदा किया है।

जनजातीय समाज के सम्मान और विकास को भी इन 12 वर्षों में राष्ट्रीय प्राथमिकता मिली है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि जनजातीय अस्मिता के सम्मान का ऐतिहासिक कदम है। पीएम जनमन योजना ने विशेष पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों तक सड़क, बिजली, पानी, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का काम शुरू किया। धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान के माध्यम से जनजातीय गांवों के समग्र विकास की दिशा में ठोस प्रयास हो रहे हैं।

छत्तीसगढ़ जैसे जनजातीय बहुल राज्य में इन योजनाओं का प्रभाव विशेष रूप से दिखाई दे रहा है। प्रदेश की बड़ी आबादी जनजातीय समाज से आती है। दूरस्थ अंचलों में रहने वाले परिवारों तक पहली बार योजनाएं व्यवस्थित रूप से पहुंच रही हैं। बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में वनोपज, पर्यटन, कौशल विकास और स्थानीय उद्यमिता के माध्यम से आजीविका के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। यह विकास केवल सड़क और भवन का विकास नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान, भागीदारी और भरोसे का विकास है।

महिला सशक्तीकरण भी मोदी सरकार के 12 वर्षों की प्रमुख उपलब्धि रही है। उज्ज्वला, जन-धन, स्वच्छ भारत, जल जीवन मिशन और मातृशक्ति से जुड़ी योजनाओं ने महिलाओं के जीवन को सरल बनाया। नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक के जरिये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को नई दिशा देने का प्रयास हुआ। जब महिला सशक्त होती है तो परिवार, समाज और राष्ट्र तीनों मजबूत होते हैं।

अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्विकास और केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण परियोजना जैसे कार्यों ने विकास भी, विरासत भी की अवधारणा को साकार किया है। योग, आयुर्वेद और भारतीय परंपराओं को विश्व स्तर पर नई प्रतिष्ठा मिली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 12 वर्ष सेवा, सुशासन और संकल्प के वर्ष रहे हैं। इन वर्षों ने यह सिद्ध किया है कि मजबूत नेतृत्व, स्पष्ट नीति और जनभागीदारी से देश की दिशा बदली जा सकती है। गरीबी से मुक्ति, नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार, जनजातीय विकास, डिजिटल क्रांति, आधुनिक अवसंरचना और सांस्कृतिक आत्मविश्वास सबने मिलकर विकसित भारत की मजबूत नींव रखी है। आज भारत केवल आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि आत्मविश्वास के साथ दुनिया को दिशा भी दे रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 का संकल्प अवश्य सिद्ध होगा। ।•••

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व
समृद्धि के स्वर्णकाल का संकल्प

डॉ. रमन सिंह

मुझे वह अवसर भी याद है जब छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रम में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई स्वयं उपस्थित हुए थे। उन्होंने तब भी कहा था कि गरीब का सम्मान और उसकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति ही सुशासन का सबसे बड़ा आधार है।

10 जून 2026 भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। यह केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास, आशाओं और आकांक्षाओं की विजय है।

मुझे आज भी वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का वह उद्घोष याद है जब उन्होंने कहा कि अंधेरा छँटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 1984 में जब भाजपा केवल दो सीटों पर सिमट गई, तब विरोधियों ने उपहास किया, लेकिन हम कार्यकर्ताओं का विश्वास अडिग था। हमें भरोसा था कि यह संघर्ष एक दिन राष्ट्रव्यापी जनआंदोलन बनेगा और फिर वर्ष 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 282 सीटों के ऐतिहासिक जनादेश ने उस विश्वास को साकार कर दिया। 26 मई 2014 को जब श्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब स्पष्ट हो गया था कि यह केवल सरकार का नहीं, बल्कि राष्ट्र के विचार का परिवर्तन है। यह राजनीति को सत्ता से सेवा की ओर ले जाने का संकल्प था। प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी जी द्वारा प्रारंभिक फैसलों में एक संकल्प था "स्वच्छ भारत अभियान "जिसे मैं मोदी जी की सबसे दूरदर्शी निर्णयों में से एक मानता हूँ।

15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए मुझे नरेंद्र भाई मोदी के साथ अनेक अवसरों पर काम करने और संवाद करने का अवसर मिला। मैंने उन्हें बहुत निकट से देखा है, एक साधारण परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक पद तक पहुंचे मोदी जी आज भी गांव, गरीब, किसान और वंचित वर्ग की पीड़ा को उसी संवेदनशीलता से समझते हैं। यही कारण है कि वे केवल एक राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आशा के प्रतीक बन चुके हैं।

मुझे वह अवसर भी याद है जब छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रम में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई स्वयं उपस्थित हुए थे। उन्होंने तब भी कहा था कि गरीब का सम्मान और उसकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति ही सुशासन का सबसे बड़ा आधार है। आज जब श्री मोदी जी के नेतृत्व में 81 करोड़ से अधिक देशवासियों को निःशुल्क राशन मिल रहा है, तब उनकी वही संवेदनशील सोच राष्ट्रीय नीति का रूप ले चुकी है।

पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास का लाभ सीधे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश के 60 करोड़ परिवारों को 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पक्के घर प्राप्त हुए हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए 9.32 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे पहुँची है। वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली, तब भारत विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। आज, मात्र एक दशक के भीतर, भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यह परिवर्तन किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व, साहसिक आर्थिक सुधारों और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने वाली नीतियों का प्रतिफल है। आज भारत लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व मंच पर आत्मविश्वास के साथ खड़ा है और तेजी से 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बीच भी भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है। यह केवल विकास दर का विषय नहीं, बल्कि विश्व समुदाय द्वारा भारत और उसके नेतृत्व पर व्यक्त किए जा रहे बढ़ते विश्वास का प्रमाण है।

प्रधानमंत्री मोदी जी की एक बड़ी विशेषता यह रही है कि उन्होंने आर्थिक विकास को केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहने दिया। उनके नेतृत्व में विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आंकलनों के अनुसार पिछले वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। यह उपलब्धि करोड़ों परिवारों के जीवन में आए उस सकारात्मक परिवर्तन की कहानी है, जहाँ सरकारी योजनाएँ कागजों से निकलकर लोगों के जीवन का हिस्सा बनीं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के विकास को केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से भी जोड़ा है। अयोध्या में भव्य श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्विकास, उज्जैन में महाकाल लोक का सृजन और चारधाम परियोजना जैसे कार्य केवल अधोसंरचना विकास नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण के प्रतीक हैं।

वर्ष 2014 से पहले जब देश पर आतंकवादी हमले होते थे, तब देशवासी केंद्र सरकार की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखते थे, लेकिन अक्सर उन्हें निराशा ही हाथ लगती थी। आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख सीमित प्रतिक्रियाओं तक ही दिखाई देता था लेकिन 2014 के बाद यह तस्वीर बदली तो इसका कारण सिर्फ मोदी जी की नीतियां हैं। कश्मीर को धारा 370 के जाल से निकालकर भारतीय संविधान की मर्यादा में शामिल करने का ऐतिहासिक निर्णय श्री मोदी जी द्वारा असंभव को संभव करने का एक अद्भुत उदाहरण है। इसके साथ ही सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिन्दूर से आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक नीति ने दुनिया को यह संदेश दिया कि नया भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। वहीं दशकों से भारत माता की पीड़ा बने नक्सलवाद को समूल नाश करने के लिए श्री मोदी जी के प्रभावी अभियानों ने 'नक्सल मुक्त भारत'के लक्ष्य को न सिर्फ साकार किया है बल्कि कभी नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने न केवल देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, बल्कि वे देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सैनिकों के त्याग और समर्पण का सम्मान करते हुए सीमा पर जवानों के साथ दीपावली मनाकर यह संदेश दिया है कि देश की सुरक्षा में जुटा प्रत्येक जवान केवल सीमा का प्रहरी नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास और सम्मान का प्रतीक है।

श्री मोदी जी ने अपने वादों को पूरा करते हुए देश का विश्वास जीता है, इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने केवल चुनावी सफलताएँ ही प्राप्त नहीं की है, बल्कि देश के राजनीतिक भूगोल को भी नई दिशा दी है। पिछले एक दशक में भाजपा का संगठनात्मक विस्तार अभूतपूर्व रहा है। आज देश के 22 राज्यों में भाजपा एवं उसके सहयोगी दलों की सरकारें हैं, 1700 से अधिक विधायक, लोकसभा में 240 सांसद और राज्यसभा में 113 सांसद करोड़ों देशवासियों के उस विश्वास का प्रतिनिधित्व करते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और भाजपा की विकासोन्मुखी राजनीति के प्रति निरंतर समर्पित हैं।

वास्तव में राजनीतिक सफलता का यह विस्तार प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जनता के बढ़ते विश्वास का ही प्रतिबिंब है। यही विश्वास उन्हें आज भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने लगातार निर्वाचित कार्यकाल के 4399 दिन पूर्ण कर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ चुके हैं। यह उपलब्धि केवल किसी व्यक्ति या दल की विजय नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक भारत में जनता द्वारा बार-बार व्यक्त किए गए विश्वास की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति है।

जब मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्षों के कार्यकाल को देखता हूँ तो मुझे यह केवल एक सरकार का कार्यकाल नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास, विकास और वैश्विक प्रतिष्ठा के पुनर्जागरण का कालखंड दिखाई देता है। गरीब कल्याण से लेकर आर्थिक प्रगति तक, अधोसंरचना निर्माण से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, सांस्कृतिक पुनर्जागरण से लेकर वैश्विक नेतृत्व तक हर क्षेत्र में भारत ने नई ऊँचाइयों को स्पर्श किया है।

भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चौथे कार्यकाल के दौरान भारत विकसित राष्ट्र बनने की अपनी यात्रा को और अधिक गति देगा। देश की जनता ने पिछले वर्षों में जिस नेतृत्व, नीयत और परिणामों को देखा है, वह विश्वास आने वाले वर्षों में और अधिक मजबूत होगा। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत न केवल विश्व की अग्रणी आर्थिक शक्तियों में शामिल होगा, बल्कि 21वीं सदी में मानवता को दिशा देने वाले राष्ट्र के रूप में भी अपनी पहचान स्थापित करेगा। ।•••

संकल्पों के सिद्धि का इतिहास गढ़ता नवीन भारत

सी. पी. राधाकृष्णन

अब हमें तिरुवल्लुवा के इन शब्दों की सच्चाई प्रत्यक्ष देखने का अवसर मिल रहा है 'जो अपने संकल्प में अडिग रहते हैं, वे वह प्राप्त करते हैं जिसकी उन्होंने कल्पना की होती है।' भारत ने पिछले एक दशक में जो प्रगति की है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी और अनिश्चितताओं से जूझ रही है, तब भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती और गति के साथ आगे बढ़ रही है। सरकार और जनता के साझा प्रयासों ने इस दौर को निरंतर विकास का युग बना दिया है।

जब मैं तिरुपुर के स्कूल में पढ़ता था, तब मेरे मन में देश को लेकर अनेक सपने थे। मैं अक्सर सोचता था कि भारत अपनी महानता क्या पुनः प्राप्त करेगा? वह विश्व मंच पर एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में कब उभरेगा? हमारे गरीब भाई-बहनों को सम्मानजनक जीवन कब मिलेगा? आज यह देखकर प्रसन्नता होती है कि किशोरावस्था में देखे गए वे सपने धीरे-धीरे साकार हो रहे हैं। मैं स्वयं को स्वामी विवेकानंद के इन शब्दों की याद दिलाता था 'उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। तमिलनाडु की धरती से निकले स्वामीजी के ये शब्द हर व्यक्ति में देशभक्ति और समर्पण की भावना जगाने की अद्भुत शक्ति रखते हैं। मेरा सदैव विश्वास रहा कि जब भारत अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ेगा तब वह पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला राष्ट्र बनेगा। पिछले एक दशक में हमारा देश जिस ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ा है, वह अत्यंत प्रेरणादायक है।

अब हमें तिरुवल्लुवा के इन शब्दों की सच्चाई प्रत्यक्ष देखने का अवसर मिल रहा है 'जो अपने संकल्प में अडिग रहते हैं, वे वह प्राप्त करते हैं जिसकी उन्होंने कल्पना की होती है।' भारत ने पिछले एक दशक में जो प्रगति की है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी और अनिश्चितताओं से जूझ रही है, तब भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती और गति के साथ आगे बढ़ रही है। सरकार और जनता के साझा प्रयासों ने इस दौर को निरंतर विकास का युग बना दिया है। कभी कमजोर अर्थव्यवस्था माना जाने वाला भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और शीघ्र ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विकास समावेशी रहा है। पिछले एक दशक में लगभग 25 करोड़ भारतीय अत्यधिक गरीबी से बाहर निकलकर सम्मानपूर्ण जीवन जीने में सक्षम हुए हैं। गरीब और बेघर लोगों के लिए लगभग 4 करोड़ पक्के घर बनाए गए हैं। 12 करोड़ से अधिक लोगों को पाइप से पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। देश ने खुले में शौच से मुक्त बनने का संकल्प लिया था और मात्र 60 महीनों में 60 करोड़ लोगों तक यह सुविधा पहुंचाई गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है, जिस पर लगभग 2.3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बचपन में मैंने गांवों में इलाज के अभाव में लोगों को परेशान होते देखा है। आज आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। परिणामस्वरूप 44 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त हुआ है। केवल पिछले एक वर्ष में ही 2.5 करोड़ लोगों ने इस योजना के तहत निःशुल्क उपचार प्राप्त किया।

हमारे किसानों ने अपनी मेहनत से 35 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन कर भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक देश बना दिया है। चावल उत्पादन में भी भारत अग्रणी देशों में शामिल है और निर्यात के माध्यम से विश्व से जुड़ रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जा चुकी है। आज नारी शक्ति को देश के विकास में पूरी भागीदारी के अवसर मिल रहे हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदी' बन चुकी है। कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, तकनीक और अंतरिक्ष अनुसंधान तक महिलाओं ने अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। अब महिलाएं सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन प्राप्त कर रही हैं और युद्धक भूमिकाओं में भी

योगदान दे रही हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी को और मजबूत करेगा। जब मैं देशभर में लखपति

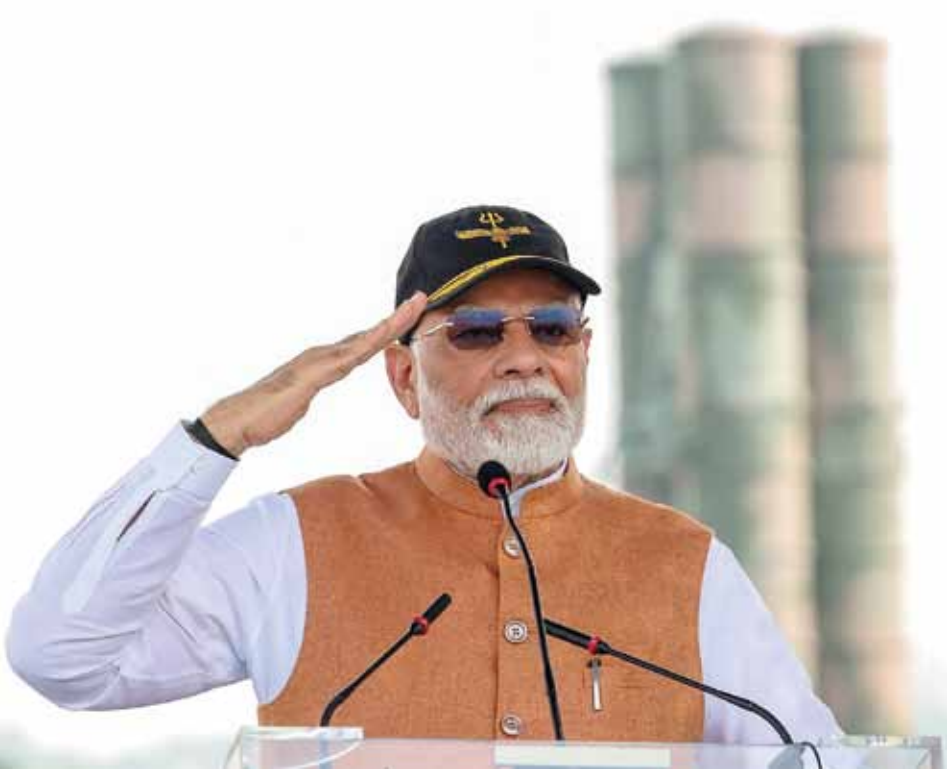

दीदियों और नमो ड्रोन दीदियों से मिलता हूं, तब उनके चेहरे पर आशा और आत्मविश्वास की चमक दिखाई देती है। महिलाओं के जीवन को सहज बनाने के लिए लगभग 2 करोड़ नए एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। युवाओं को स्टार्टअप्स की ओर उत्साहपूर्वक बढ़ते देखकर कवि सुब्रमण्यम भारती के शब्द याद आते हैं- आओ अपने सपनों को साकार करो, पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़े और समृद्ध बने, आओ, कुछ महान करके दिखाओ। पिछले दस वर्षों में युवाओं के लिए 13 नए आईआईटी स्थापित किए गए हैं, जिससे इनकी कुल संख्या 23 हो गई है। इसी प्रकार आईआईएम की संख्या 13 से बढ़कर 21 हो गई है। एम्स की संख्या 7 से बढ़ाकर 23 हो चुकी है तथा मेडिकल कॉलेजों को संख्या बढ़कर 823 हो गई है। मेडिकल सीटों की संख्या 51,348 से बढ़कर 1.29.603 हो जाना अत्यंत गर्व का विषय है।

भारत विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय रेलवे का लगभग 99 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है। 164 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों ने रेल यात्रा के नए युग की शुरुआत की है। हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 163 हो गई है और उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को सुलभ बनाया है। तमिलनाडु के लिए रेलवे बजट, जो एक दशक पहले लगभग 880 करोड़ रुपए था, बढ़ाकर 2026-27 में 7,600 करोड़ रुपए हो गया है। रामेश्वरम और पंबन के बीच बना नया पंबन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल रिफ्ट ब्रिज है, जिसने आध्यात्मिक पर्यटन और आर्थिक विकास को नई गति दी है। चिनाब ब्रिज और बोगीबील पुल जैसे निर्माण आधुनिक भारत की नई पहचान बन चुके हैं।

देशभर में चार और आठ लेन सड़कों के साथ-साथ सुदूर गांवों तक सड़क संपर्क को मजबूत किया गया है। तमिलनाडु में पिछले दस वर्षों में 4,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में लगभग 7,200 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री की प्रगति योजना के तहत इन परियोजनाओं की लगातार निगरानी की गई है। प्री-मेट्रिक और पोस्ट मेट्रिक छात्रवृति योजनाओं तथा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों ने अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को विशेष लाभ पहुंचाया है। मेरा विश्वास रहा है कि विकास केवल कुछ वर्गों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें सभी क्षेत्रों की समान भागीदारी सुनिश्चित होनी साहिए। जो सीमावर्ती गांव कभी देश के अंतिम गांव कहे जाते थे, वे आज बाइब्रेंट विलेज योजना के तहत देश के प्रथम गांव बनकर उभर रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों को देश की 'अष्टलक्ष्मी कहना अत्यंत सार्थक है। नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम की यात्राओं के दौरान वहां परिवहन और आधारभूत संरचना में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला। विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां हम सभी को गर्व से भर देती हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने स्वदेशी वैक्सीन विकसित कर न केवल अपने नागरिकों को निःशुल्क टीके उपलब्ध कराए, बल्कि 100 से अधिक देशों को भी सहायता दी। चंद्रयान-3 की सफलता ने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के नए युग में पहुंचा दिया है। एआई के क्षेत्र में वैश्विक कंपनियां भारत को अपना केंद्र बना रही हैं। भारत अब सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में भी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण मॉडल बनकर उभर रहा है। मोबाइल फोन उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। जो भारत कभी मोबाइल फोन आयात करता था वही आज 300 करोड़ अमरीकी डॉलर मूल्य के मोबाइल फोन निर्यात कर रहा है। यह उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों के समृद्ध भविष्य की मजबूत नींव हैं। देश ने दशकों तक आतंकवाद, उग्रवाद और वामपंथी चरमपंथ जैसी चुनौतियों का सामना किया है। दृढ़ नीतियों और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन से आज इन क्षेत्रों में शाति और विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2047 तक, स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण होने पर, भारत एक विकसित और विश्वको मार्गदर्शन करने वाला राष्ट्र बने। यही कालखंड अमृत काल है। जिस प्रकार स्वतंत्रता सेनानियों के हृदय में आजादी का संकल्प था, उसी प्रकार आज के युवाओं के मन में राष्ट्र निर्माण का संकल्प होना चाहिए। यदि युवाओं के विचार और प्रयास देशभक्ति उच्च आदतों और श्रेष्ठ चरित्र के साथ आगे बढ़ेंगे तो 2047 तक विकसित भारत का सपना अवश्य साकार होगा। स्वामी विवेकानंद के शब्द आज भी हमें प्रेरित करते हैं- 'मेरे भाइयों, आइए हम सब मिलकर कड़ी मेहनत करें। यह सोने का समय नहीं है। भारत का भविष्य हमारे प्रयासों पर निर्भर करेगा। आइए, हम सब मिलकर अपनी मेहनत, समर्पण और संकल्प से एक विकसित भारत का निर्माण करें। ●●●

संभव नहीं मोदी और नेहरू की तुलना

डॉ. सुधांशु त्रिवेदी

15 अगस्त 1947 को नेहरू स्वतंत्र भारत में सरकार का नेतृत्व संभालते हैं। इसके बाद जम्मू-कश्मीर का एक हिस्सा, अक्साई चिन और मानसरोवर भारत से अलग हो जाता है। पाकिस्तान कश्मीर पर आक्रमण कर देता है और नेहरू स्वयं कश्मीर को यूएन ले जाते हैं और संविधान में अनुच्छेद 370 शामिल करते हैं। दूसरी तरफ मोदी के नेतृत्व में अगस्त 2019 में जब वही अनुच्छेद 370 समाप्त होता है, तब पाक और उसके तमाम अंतरराष्ट्रीय आका एक भी प्रस्ताव भारत के खिलाफ यूएन में नहीं ला पाते।

देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और वर्तमान पीएम नरेन्द्र मोदी की तुलना का तथ्यात्मक विश्लेषण करना चाहिए। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत नए कांग्रेस अध्यक्ष को अंग्रेजों के अधीन अंतरिम सरकार का नेतृत्व करना था। अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्यसमिति में राज्यों से नाम आए। उनमें एक वोट कृपलानी एवं पट्टाभी सीतारमैया को और शेष सारे वोट सरदार पटेल को थे और नेहरू जी को शून्य वोट। इसके बावजूद गांधीजी की कृपा से नेहरू प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने। ये संदर्भ नेहरू सेलेक्टेड वर्क्स, मौलाना आजाद, सरदार पटेल और कृपलानी जी की पुस्तकों में वर्णित हैं। इसके बाद वेवल द्वारा ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर 2 सितंबर, 1946 को नेहरू ने अंतरिम सरकार और 15 अगस्त, 1947 को माउंटबेटन द्वारा शपथ लेकर नेतृत्व संभाला। इसके बाद 13 मई, 1952 को वे आम चुनाव जीतकर आए। गांधीजी की कृपा, अंग्रेजों की सुविधा और विपक्ष-विहीन चुनाव से होते हुए वे पीएम पद तक पहुंचे। इसके विपरीत 13 सितंबर, 2013 को भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में मोदी सर्वसम्मति से पीएम पद के उम्मीदवार बने। संपूर्ण पार्टी का समर्थन और उसके बाद प्रबल जनसमर्थन प्राप्त कर बिना किसी कृपा, सुविधा के पूर्ण बहुमत हासिल करके उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक राजनीति का एक नया अध्याय लिखा। इस तरह मोदी की नेहरू से तुलना बेमानी है।

जहां नेहरू कश्मीर मसले को यूएन ले जाते हैं और संविधान में अनुच्छेद 370 शामिल करते हैं, वहीं मोदी 370 को समाप्त करते हैं

चीन जब तिब्बत में था और चीनी सेना के सामने भुखमरी की चुनौती थी, तब तिब्बत में सड़कें चीन की तरफ नहीं, बल्कि भारत की तरफ बेहतर थीं। नेहरू ने चीनी सेना को 3,500 टन चावल भिजवाया। 1947 में चीन के पास वायु सेना नहीं थी, भारत के पास थी। चीन की वायु सेना 1949 में बनी। फिर भी 1962 में 19 नवंबर, 1962 को नेहरू ने अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी को पत्र लिखकर उनसे सिर्फ विमान ही नहीं मांगे, बल्कि पूर्वोत्तर बचाने के लिए भारतीय वायु सेना की एक प्रकार से कमान अमेरिका को देने के लिए लिखा। अमेरिका में भारत के तत्कालीन राजदूत नेहरू जी के भतीजे बीके नेहरू ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि यह पत्र इतना अपमानजनक था कि राष्ट्रपति के सलाहकार को देने के बाद वे अपने को रोने से नहीं रोक पाए।

जब गलवान में चीन के साथ संघर्ष में हमारे 20 जवान बलिदान हुए तो अंतरराष्ट्रीय स्रोतों के अनुसार चीन के 55-60 सैनिक मारे गए। संभवतः बड़ी संख्या की वजह से ही चीन ने अपने मारे गए सैनिकों की सूची कभी जारी ही नहीं की। बालाकोट के समय पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वहां के एक सांसद ने कहा था कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री बैठे थे, सेना प्रमुख आए। उनके पांव कांप रहे थे और उन्होंने कहा, खुदा का वास्ता है कि अभिनंदन को वापस कर दो, वरना रात 9 बजे तक भारत आक्रमण कर देगा। साफ है कि नेहरू की लचर सैन्य नीति और मोदी की सुदृढ़ सैन्य नीति की कोई तुलना नहीं।

15 अगस्त 1947 को नेहरू स्वतंत्र भारत में सरकार का नेतृत्व संभालते हैं। इसके बाद जम्मू-कश्मीर का एक हिस्सा, अक्साई चिन और मानसरोवर भारत से अलग हो जाता है। पाकिस्तान कश्मीर पर आक्रमण कर देता है और नेहरू स्वयं कश्मीर को यूएन ले जाते हैं और संविधान में अनुच्छेद 370 शामिल करते हैं। दूसरी तरफ मोदी के नेतृत्व में अगस्त 2019 में जब वही अनुच्छेद 370 समाप्त होता है, तब पाकिस्तान और उसके तमाम अंतरराष्ट्रीय आका एक भी प्रस्ताव भारत के खिलाफ यूएन में नहीं ला पाते।

नेहरू ने अंग्रेजों के जाने के बाद भी भारत के स्वाभिमान को उठने नहीं दिया। उन्होंने सोमनाथ

एआई इमेज

मंदिर के पुनरुद्धार का विरोध किया और मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। नेहरू ने 17 मार्च, 1959 को अपने भाषण में कहा था कि दक्षिण भारत के विशाल मंदिरों के गलियारों में वे डिप्रेस्ड महसूस करते हैं और ताजमहल के सामने आनंद से सराबोर रहते हैं। दूसरी तरफ मोदी ने काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, महाकाल, करतारपुर साहब कोरिडोर और श्रीरामलला के भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त कर भारत के स्वाभिमान को जगाया।

नेहरू ने विज्ञान और तकनीक के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाए, पर उनका विचार पश्चिम का पिछलग्गू बनने से प्रेरित रहा। भारत कर सकता है, यह आत्मविश्वास उनमें नहीं था। यदि 1950 में ही एम्स के साथ आयुर्वेदिक एम्स भी बन गया होता, जो मोदी ने बनवाया तो आज हम चिकित्सा के इस क्षेत्र में विश्व में अग्रणी होते। तब मलेरिया की हर्बल दवाई का नोबेल पुरस्कार चीन और उपवास रखने पर शरीर को लाभ मिलने का नोबेल पुरस्कार 2016 में जापान को नहीं जाता। वर्ष 1959 में राधा कृष्णन समिति की अनुशंसा पर देश में कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनने का विचार आया और पंतनगर देश का ऐसा पहला विश्वविद्यालय बना। यह उचित विचार था, पर कृषि में पश्चिम के अंधानुकरण के साथ यदि भारत की परंपरागत जैविक कृषि के लिए भी विश्वविद्यालय बना होता तो आज दुनिया जिस जैविक कृषि के लिए लालायित है, उसमें हम विश्व का नेतृत्व कर रहे होते। मोदी ने आयुर्वेद को विश्व के पटल पर मान्यता दिलवाई और जैविक कृषि का अभियान शुरू किया। होमी भाभा के प्रयासों से भारत नेहरूजी के समय में ही परमाणु शक्ति बन सकता था, पर नेहरू ने ऐसा नहीं किया। मोदी ने भारत की जल, थल और वायु तीनों सेनाओं को आणविक शक्ति से लैस किया।

16 मई, 2014 को जब मोदी के नेतृत्व में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला तो 18 मई को लंदन के अखबार संडे गार्डियन ने अपने संपादकीय का शीर्षक दिया, 'नियति के साथ भारत का दूसरा मिलन।' यह 15, अगस्त 1947 को नेहरू के भाषण 'नियति के साथ भारत का मिलन' से तुलना थी। अखबार ने लिखा कि 1947 के बाद जिन दलों का शासन रहा, वे ब्रिटिश विरासत के विचार से प्रेरित रहे थे। अब एक ऐसे दल के हाथ में पूर्ण सत्ता आई है, जिस पर कोई ब्रिटिश प्रभाव नहीं है। उसने यह भी लिखा कि 16 मई, 2014 का दिन भारत के इतिहास में इस रूप में अंकित होना चाहिए, जिस दिन अंग्रेज अंतिम और निर्णायक रूप से भारत से विदा हो गए। ।•••

12 वर्षों का स्वर्णिम काल समृद्धि को समर्पित : साय

भाजपा ने जीत का शतक बनाया, कांग्रेस ने हार का : गिरिराज सिंह

प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनादेश के साथ निर्वाचित होकर लगातार 12 वर्षों से प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से मोदीजी को बधाई देते हुए श्री साय ने कहा कि 12 वर्षों का यह कार्यकाल स्वर्णिम और ऐतिहासिक रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी खुद को प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक कहते हैं। 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हैं। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' को मूलमंत्र मानते हुए दिन और रात 140 करोड़ भारतवासियों की सेवा करते हैं। श्री साय श्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शानदार 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित मीडिया कॉन्क्लेव को सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है। एक समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण हो रहा है। एक ऐसा भारत जो किसी को छेड़ता नहीं है और छेड़ने वाले को छोड़ता भी नहीं है। दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है। ऐसे नए भारत का निर्माण प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में हुआ है। 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने देश के विकास के लिए अद्भुत काम किए हैं। अगर गरीब कल्याण की बात करें तो सरकार ने जन-धन योजना के तहत 58 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले, जिनमें 32 करोड़ से ज्यादा खाते सिर्फ महिलाओं के हैं। कोरोना जैसी महामारी के मुश्किल वक्त से लेकर अब तक 81 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इलाज के खर्च से गरीब को बचाने के लिए आयुष्मान भारत योजना में 60 करोड़ से ज्यादा हेल्थ कार्ड बने हैं, जिससे मुफ्त इलाज की गारंटी मिली है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से भी 58 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक मजबूत सुरक्षा कवच मिला है। श्री साय ने कहा कि गरीबों के जीवन को आसान बनाने के लिए पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्के मकान दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना के जरिए 11 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देकर धुएँ से आजादी दी गई है।

18 लाख वंचित परिवारों को आवास देने का संकल्प पूरा कर रही सरकार : साय

मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास की अवधारणा को धरातल में उतारने की दिशा में प्रधानमंत्री श्री मोदी के संवेदनशील

नेतृत्व का आभार माना और कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए यह सौभाग्य का विषय है कि यहाँ पर हमारी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालन में तेजी से आगे बढ़ रही है। हम लोगों ने 18 लाख परिवारों, जो पिछली सरकार में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित हो गए थे, उनको भी 2 साल में आवास देने का काम किया है। 10.60 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने की दिशा में काम करते हुए रोज 1600 प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं। 10.08 लाख आवास ढाई वर्षों के अंदर में बने हैं। इसी प्रकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत छत्तीसगढ़ में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर सहकारी बैंक द्वारा ऋण दिया जा रहा है, जिससे हमारे यहाँ के किसान लाभान्वित हो रहे हैं।प्रधानमंत्री श्री मोदी के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का रेलवे बजट भी लगातार बढ़ा है। 50 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का रेलवे का काम छत्तीसगढ़ में चल रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की मंशा के अनुरूप हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर करें इसके लिए उड़ान योजना के तहत छत्तीसगढ़ में भी सेवाएँ शुरू की गई है।

हमने ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक जीत का शतक बनाया : सिंह

केन्द्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने मीडिया कॉन्क्लेव में कहा कि हमने ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक राष्ट्रीय सरकार तक जीत का शतक बनाया और कांग्रेस ने हार का शतक बनाया। 22 राज्यों में हमारी सरकार है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने 12 वर्षों के कार्यकाल में विकास के साथ विरासत का संरक्षण और विरासत के साथ विकास का संवर्धन करने का काम किया है। श्री मोदी ने पहली बार वन नेशन वन टैक्स की व्यवस्था लागू करके भारत की अर्थव्यवस्था सुधारने की दिशा में अहम कार्य किया। आज दुनिया के 22 देश भारत के साथ भारतीय मुद्रा रुपए में कारोबार कर रहे हैं। यह हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। 16 लाख करोड़ रुपए के बजट को 53.5 लाख करोड़ रुपए तक लाने का काम मोदी-सरकार ने किया है। श्री सिंह ने कहा कि आज के दौर में दुनिया के सामने भारत के इकॉनॉमी को 10वें स्थान से लाकर चौथे-छठे स्थान पर लाने का काम किया है। 2 ट्रिलियन के इकॉनॉमी को 4.25 पर लाने का काम किया है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाया गया है। कांग्रेस शासन काल में गरीब मिट गए, लेकिन गरीबी नहीं मिटी थी। श्री सिंह ने कहा कि आज दुनिया का हर देश श्री मोदी से हाथ मिलाना चाहता है। आज पूरी दुनिया कह रही है कि भारत की विदेश नीति सबसे अच्छी है। श्री मोदी देश के लिए हितकर होता है, वही करते हैं। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी व रायपुर शहर जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर भी उपस्थित थे।

जनादेश, जनकल्याण और सुशासन का नया कीर्तिमान : किरण देव

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 12 वर्षों के सफल कार्यकाल को विकास, सुशासन और जनकल्याण का स्वर्णिम युग बताया है। जगदलपुर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार जनादेश प्राप्त कर देश के प्रधानमंत्री के रूप में 12 वर्षों का ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण कार्यकाल पूरा किया है, जो लोकतंत्र में जनता के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने विकास के साथ-साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली परंपराओं के संरक्षण को भी समान महत्व दिया है।

मोदी के 12 वर्षों में देश की दशा और दिशा बदली : अरुण साव

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 12 वर्षों के सफल कार्यकाल पर बधाई देते हुए कहा कि इस अवधि में देश की दशा और दिशा दोनों बदली हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय राजनीति का स्वरूप विकास, सुशासन और जवाबदेही आधारित हुआ है। अब राजनीति केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदर्शन और परिणामों पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है, जिससे करोड़ों लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है।

आईईडी मुक्त गांव अभियान का विस्तार होगा : विजय शर्मा

उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के सफल कार्यकाल को देश के विकास, सुशासन और राष्ट्रीय स्वाभिमान का स्वर्णिम काल बताया। दुर्ग सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास, सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण और राष्ट्रीय गौरव के क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। श्री शर्मा ने बस्तर में नक्सल उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे 'आईईडी मुक्त गांव' अभियान की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि इस मॉडल को अब मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़ जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा, जिससे सुरक्षा और विकास को नई मजबूती मिलेगी। ।•••

मोदी सरकार के 12 वर्ष

विकास, सुशासन और आत्मनिर्भर भारत की गौरवगाथा

केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 वर्ष पूर्ण होने के साथ भारत ने विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया अध्याय लिखा है। इन वर्षों में देश ने आधारभूत संरचना, डिजिटल क्रांति, सामाजिक कल्याण, आर्थिक सुधार और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी नीतियों के परिणामस्वरूप जनधन योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत जैसी पहलें करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सफल रही हैं। आधुनिक एक्सप्रेस-वे, वंदे भारत ट्रेनें, सेमीकंडक्टर मिशन और भारतनेट जैसी परियोजनाओं ने विकसित भारत की मजबूत नींव रखी है। आज भारत विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है और 'विकसित भारत 2047' के संकल्प की ओर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। यह 12 वर्षों की यात्रा केवल सरकार की उपलब्धियों की नहीं, बल्कि नए भारत के निर्माण की गाथा है।

लोक सेवा ही संकल्प

गरीबी उन्मूलन

- **25+** करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले (2014 के बाद)
- **04+** करोड़ पक्के मकान - PM आवास योजना
- **81+** करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज (PM गरीब कल्याण अन्न योजना)
- **58+** करोड़ जन-धन खाते - बैंकिंग क्रांति

स्वच्छता एवं बुनियादी सुविधाएं

- **12** करोड़ से अधिक शौच मुक्त शौचालय निर्मित, 5 लाख गांव खुले में
- **16** करोड़ घरों को नल से जल जल जीवन मिशन
- **11** करोड़ एलपीजी कनेक्शन - पीएम उज्ज्वला योजना (धुआं मुक्त रसोई)

छोटे उद्यमी एवं वंचित वर्ग

- **57** करोड़ से अधिक स्वरोजगार गारंटी मुक्त मुद्रा लोन से मिल रहा
- **74** लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों को PM स्वनिधि लोन
- **15** हजार करोड़ स्टार्टअप इंडिया - SC/ST उद्यमियों को लोन

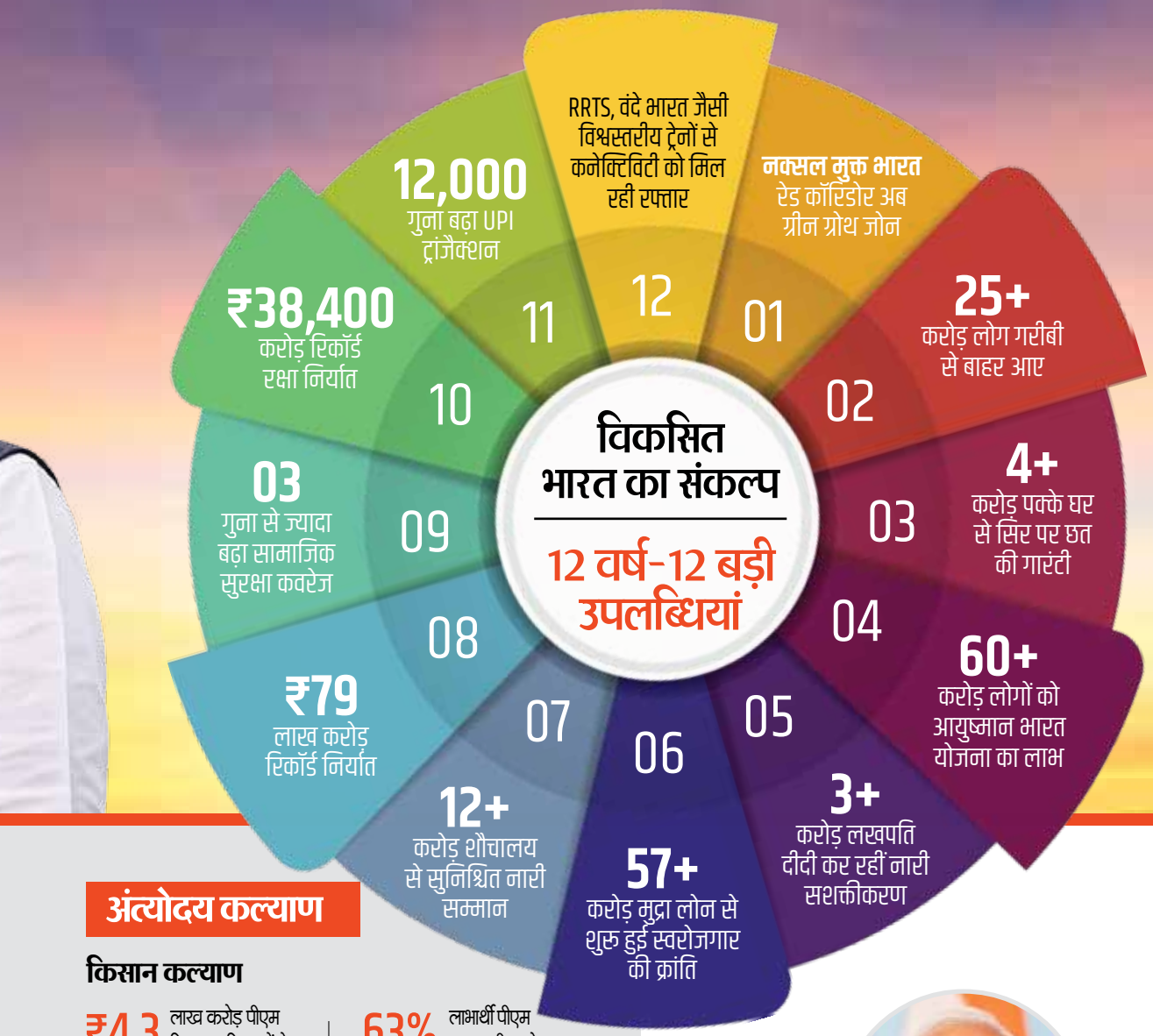

अंत्योदय कल्याण

किसान कल्याण

₹4.3 लाख करोड़ पीएम किसान- किसानों के खाते में राशि सीधा ट्रांसफर

63% लाभार्थी पीएम फसल बीमा योजना - एससी/एसटी/ओबीसी किसान

90% सब्सिडी ₹266/ बैग यूरिया-किसानों को राहत

71% वृद्धि खाद्यान्न उत्पादन - रिकॉर्ड 12,000+ लाख मीट्रिक टन

मध्यम वर्ग - नई उड़ान

₹12.75 लाख आयकर छूट सीमा (2 लाख रुपए से 6 गुना हुई)

₹2+ लाख प्रति व्यक्ति वार्षिक आय (86,000 से दोगुनी)

01 करोड़ PM सूर्य घर - रूफटॉप सोलर, मुफ्त बिजली का लक्ष्य

स्वास्थ्य - आयुष्मान भव

60+ करोड़ तक मुफ्त इलाज PM जन आरोग्य योजना ₹5 लाख

03 गुना 8 से 23 हुई AIIMS की संख्या मेडिकल शिक्षा सीटें बढ़ीं

7.3+ करोड़ पीएम सुरक्षित मातृत्व - गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच

"भारत आज 'विकास' और 'सुशासन' (गुड गवर्नेंस) के दम पर एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। सरकार की नीतियां पारदर्शी, तेज और गरीब-कल्याण को समर्पित हैं, जिससे हर नागरिक का जीवन सुगम बना है। डिजिटल क्रांति, मजबूत बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) और वैश्विक मंच पर बढ़ती साख ने देश के आत्मविश्वास को बढ़ाया है। 'आत्मनिर्भर भारत' का संकल्प केवल एक नारा नहीं, बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों का मिशन है। देश अब रक्षा, विनिर्माण और तकनीक में आत्मनिर्भर बन रहा है, जो विकसित भारत के निर्माण की नींव है।"

-नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

सशक्तीकरण से सामर्थ्य निर्माण

नारी शक्ति

32+
करोड़ महिलाओं के जन-धन खाते खोले गए

03+
करोड़ लखपति दीदी - 6 करोड़ का लक्ष्य 2030 तक

91+
लाख स्वयं सहायता समूह - 10+ करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लाभ

4.5+
करोड़ PM सुकन्या समृद्धि खाते - बेटियों का सुरक्षित भविष्य

48%
DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में महिला निदेशक

105+
करोड़ सैनिटरी पैड मात्र 1 रुपए में - जन औषधि केंद्र से मिले

महिला सशक्तीकरण- 12 वर्षों का बदलाव

918 से 929 जन्म के समय लिंगानुपात (प्रति 1000)

68 प्रतिशत से 98 प्रतिशत संस्थागत प्रसव

03 हजार से 11,000 से अधिक सुरक्षा बलों में महिला अधिकारी

12 से 26 सप्ताह पेड मैटरनिटी लीव

युवा शक्ति

भारत दुनिया का सबसे युवा देश - नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू

₹33.5 लाख करोड़ 120 बड़े स्टार्टअप्स का कुल मूल्य

₹1.60 लाख करोड़ सेमीकंडक्टर मिशन निवेश

एससी/एसटी/ओबीसी - वंचितों को वरीयता

₹15 हजार करोड़ से अधिक जनजातीय कल्याण बजट - 2014-15 से 243% अधिक

₹79 हजार करोड़ से अधिक धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

12 लाख से अधिक परिवारों तक पीएम जनमन से आवास-स्वास्थ्य-आजीविका

राष्ट्र निर्माण का मिशन

आर्थिक महाशक्ति

₹345+ लाख करोड़ GDP - वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था

27 लाख करोड़ 2024-25 में प्रत्यक्ष कर संग्रह

₹67 लाख करोड़ विदेशी मुद्रा भंडार, 11 माह का आयात कवर

₹70+ लाख करोड़ एफडीआई - 2014 से 2025 के बीच

उत्पादन एवं रोजगार

₹20+ लाख करोड़ पीएलआई योजना से बिक्री - मार्च 2026 तक

163 गुना वृद्धि मोबाइल निर्यात में भारत ने रचा नया इतिहास

12+ लाख पीएलआई योजना से रोजगार सृजित

38 देश, 9 एफटीए, वैश्विक व्यापार को नई गति

राष्ट्र प्रथम ही मंत्र

विदेश नीति - नई पहचान

G-20 अध्यक्षता
100% नेताओं की सहमति -दिल्ली घोषणा

100% भारत-न्यूजीलैंड FTA
सभी टैरिफ श्रेणी शुल्क मुक्त

39 नए दूतावास
219 मिशन 2014-2026 में विस्तार

₹70+ लाख करोड़ FDI
वैश्विक भरोसे का प्रमाण (2014-2025)

99% भारत-EU FTA
व्यापार मूल्य पर शुल्क रियायत

30+ करोड़ वैक्सीन मैत्री
99 देशों को कोविड वैक्सीन की डोज

13+ लाख करोड़ विदेशी धनराशि (रेमिटेंस) विश्व में सर्वाधिक

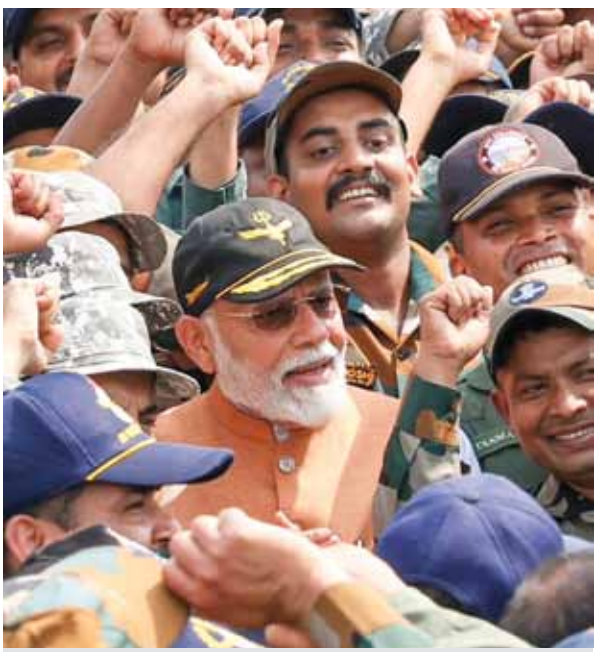

राष्ट्रीय सुरक्षा - आतंक पर जीरो टॉलरेंस

उरी, पुलवामा हमले
के बाद करारा जवाब

रक्षा निर्यात ₹38,400
करोड़ रिकॉर्ड स्तर पर

ऑपरेशन सिंदूर
आतंक के खिलाफ नई नीति

नक्सल मुक्त भारत
रेड कॉरिडोर अब ग्रीन ग्रोथ जोन

विरासत भी विकास भी

धरोहर संरक्षण

44 UNESCO विश्व धरोहर
Asia-Pacific में भारत दूसरे स्थान पर

668 कलाकृतियां
स्वदेश वापस (2014 में केवल 13 थीं)

अब 11 शास्त्रीय भाषा
2024 में पांच नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा

12+ लाख पुरावशेष
11,000+ स्मारक डिजिटल रूप में संरक्षित

गुलामी की मानसिकता से मुक्ति

राजपथ - अब कर्तव्य पथ
रेस कोर्स रोड अब लोक कल्याण मार्ग

पोर्ट ब्लेयर
अब श्री विजयपुरम

मुगल गार्डन अब अमृत उद्यान
सेंगोल नई संसद में स्थापित

भारत माता
का स्मारक सिक्का जारी

21 द्वीपों के नाम
परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर

2035 तक औपनिवेशिक
मानसिकता से पूर्ण मुक्ति का लक्ष्य

आध्यात्मिक-सांस्कृतिक पुनर्जागरण

अयोध्या - श्री राम जन्मभूमि पर नव्य-भव्य-दिव्य राम मंदिर

बुद्ध सर्किट एवं राम सर्किट तीव्र विकास

काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल महालोक, केदारनाथ धाम - पुनर्निर्माण

PRASHAD योजना 1,700+ करोड़ से तीर्थ स्थलों का विकास

योग - भारत की सॉफ्ट पावर

177 देशों ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने को दिया समर्थन

तकनीक से जन-जन तक

डिजिटल क्रांति

142 से 63वां Ease of Doing Business - वैश्विक रैंकिंग में सुधार

64 करोड़ लोगों को PMGDISHA के तहत डिजिटल साक्षरता मिली

₹22+ लाख करोड़ GST संग्रह - एक राष्ट्र एक बाजार (2024-25)

- PRAGATI प्लेटफॉर्म डिजिटल गवर्नेंस का गेमचेंजर
- Faceless Tax System - पारदर्शिता बढ़ी
- JAM Trinity (जनधन-आधार-मोबाइल) 51+ लाख करोड़ DBT

पूर्वोत्तर - अब दिल और दिल्ली के करीब

83 दौरे PM ने स्वयं पूर्वोत्तर का 83 से अधिक बार दौरा किया

'अष्टलक्ष्मी' - पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में विकास की नई कहानी

पूर्वोत्तर की अर्थव्यवस्था में 3x वृद्धि

अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में 100% रेलवे विद्युतीकरण

सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को पहली बार हवाई संपर्क प्राप्त

सामाजिक सुरक्षा का विस्तार

314 करोड़ ई-श्रम से जुड़े असंगठित कामगारों को बीमा-पेंशन

500 ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम - पिछड़े ब्लॉकों में स्वास्थ्य-शिक्षा को बढ़ावा

1 करोड़ गिग कामगारों को आयुष्मान भारत में 5 लाख का स्वास्थ्य कवच

14.3 करोड़ पासपोर्ट (2014-2025)

प्रतिवर्ष : 2014 में 91 लाख, अब 1.4 करोड़ पासपोर्ट हो रहे जारी

3.5+ लाख प्रवासी भारतीयों की मदद, Indian Community Welfare Fund से

नीति, नीयत और निष्पादन से ही गढ़ा जा रहा है छत्तीसगढ़ का भविष्य

सामान्य धारणा के विपरीत, 2005 बैच के आईएएस अधिकारी रहे ओपी चौधरी ने प्रशासनिक दक्षता और जनसंवेदनशीलता का प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रशासन के बाद राजनीति में सक्रिय रहते हुए उन्होंने वित्तीय प्रबंधन और विकास कार्यों में अपनी अलग पहचान बनाई। उनके कार्यों की चर्चा छत्तीसगढ़ के साथ अन्य राज्यों में भी होती है। स्वदेश के स्थानीय संपादक जयप्रकाश मिश्र से बातचीत में वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ के विकास, अंजोर विजन @2047, प्राथमिकताओं और चुनौतियों पर विस्तार से विचार साझा किए। जिसके संपादित अंश प्रस्तुत है।

Q अभी हाल ही में असम और बंगाल में भाजपा को सफलता मिली है। आपने जिस क्षेत्र में प्रचार की कमान संभाली, वहां जीत हुई। यह कैसे संभव हुआ?

A यह सफलता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के 12 साल के स्पष्ट विजन, परिश्रम के साथ संगठन एवं वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास का परिणाम है। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में जनसंपर्क को मजबूती से आगे बढ़ाया, लोगों की समस्याओं को समझा और भाजपा के विकास एजेंडे को पूरी तरह से जनता तक पहुंचाया। तुष्टिकरण के खिलाफ पार्टी की नीतियों और समर्पण को देखकर जनता ने भारतीय जनता पार्टी जो समर्थन दिया, वही हमारी जीत की कुंजी रही। भाजपा में हर कार्यकर्ता को जो दायित्व मिलता है, वह उसे पूरा करता है। संगठन द्वारा दिए गए दायित्वों को हमने भी पूरा किया।

Q छत्तीसगढ़ ने पिछले 25 वर्षों में जो विकास यात्रा तय की है, उसे आप कैसे देखते हैं?

A छत्तीसगढ़ ने पिछले 25 वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। हमने प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग करते हुए सतत् रोजगार सृजन, कृषि और ग्रामीण विकास के बीच संतुलन स्थापित किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना में लगातार सुधार के साथ डिजिटल नवाचारों को भी अपनाया गया, जिससे राज्य आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ा। यह यात्रा चुनौतियों से भरी रही, लेकिन हर चुनौती ने हमें नए अवसर खोजने के लिए प्रेरित किया। हमें यह समझना होगा कि विकास का पैमान सिर्फ आर्थिक वृद्धि नहीं है, सामाजिक संतुलन के साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार भी है। इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में हम सभी कार्य कर रहे हैं।

Q पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन से नवाचार लागू किए गए हैं?

A वन संरक्षण, जल और मिट्टी संरक्षण, हरित ऊर्जा प्रोजेक्ट्स और पर्यावरण-संवेदनशील औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण के साथ-साथ तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली है। फ्लाईएश के लिए जीपीएस सिस्टम और हजार्डस मेटल के छत्तीसगढ़ में लाने पर प्रतिबंध जैसे कदम उठाए गए हैं। सबसे जरूरी जन जागरुकता और जनभागीदारी है। इन पहलों को लेकर कई तरह मॉडल बनाए गए हैं।

Q राज्य के विकास के अगले चरण में कौन-से क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण होंगे?

A मैं अगले चरण की चर्चा करूं, उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में स्पष्ट नीति, साफ नीयत और मजबूत निष्पादन से ही विकसित छत्तीसगढ़ का भविष्य गढ़ा जा रहा है। अगले चरण में चार क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहला- सतत रोजगार सृजन। दूसरा- कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती। तीसरा- शिक्षा और कौशल विकास और चौथा-हरित ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण। इन चार स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करने से छत्तीसगढ़ 2047 तक समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बन सकता है।

Q 25 वर्षों की उपलब्धियों के बाद राज्य किन प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रहा है?

A चुनौतियां स्पष्ट हैं। रोजगार सृजन, औद्योगिक निवेश बढ़ाना, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना और ग्रामीण-शहरी असमानताओं को कम करना जैसे कई मुख्य मुद्दे हैं। इन सभी के समाधान के लिए हमें दीर्घकालिक, रणनीतिक और नवाचारपूर्ण नीतियां बनानी होंगी। आपने इस साल वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को देखा होगा। हम लोगों ने संकल्प (संकल्प) की थीम पर बजट प्रस्तुत किया। समावेशी विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, आजीविका और नीति से परिणाम तक की बात की गई है।

Q क्या इसमें युवा, औद्योगिकीकरण व ग्रामीण विकास हेतु खास पहलें शामिल हैं?

A बिल्कुल, युवा कौशल विकास, स्टार्टअप सेंटर, ग्रामीण उद्योग संवर्धन, स्मार्ट ग्राम परियोजनाएं और रोजगार योजनाएं इस विजन का हिस्सा हैं। हमारा उद्देश्य है कि युवा राज्य की समृद्धि के केंद्र बनें और ग्रामीण क्षेत्र भी प्रगतिशील और आत्मनिर्भर हों। नए ग्रोथ हब के रूप में स्टेट कैपिटल रीजन की स्थापना की जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों में विकास के आधार पर 50 लाख से अधिक रोजगार सृजित करना उद्देश्य है।

Q अंजोर विजन 2047 में आपकी सरकार की मुख्य प्राथमिकताएं क्या हैं?

A प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 2047 विकसित भारत के विजन से प्रभावित होकर छत्तीसगढ़ अंजोर विजन @ 2047 तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य को 2047 तक एक समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने का 25 वर्षीय रोडमैप है। इसमें अल्पकालिक, मध्यमकालिक एवं दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। राज्य को आर्थिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों तक ले जाने का लक्ष्य है। योजना की 13 प्रमुख थीम जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जीडीपी को 15 गुना बढ़ाना और 50 लाख से अधिक रोजगार सृजित करना उद्देश्य है। हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक छत्तीसगढ़ एक विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बने।

Q क्या शहरी और ग्रामीण आवास योजनाओं में अलग मॉडल अपनाए जा रहे हैं?

A हां। शहरी क्षेत्रों में फ्लैट और अपार्टमेंट मॉडल दोनों तरह के आवास लाभार्थी के द्वारा बनाए जा रहे हैं। सरकार उन्हें आर्थिक मदद करती है। लाभार्थी अपनी पसंद से आवास बनाते हैं। लाभार्थी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी किफायती, पर्यावरण-संवेदनशील व स्थानीय संसाधनों पर आधारित घर बनाए जा रहे हैं।

Q छत्तीसगढ़ की वर्तमान वित्तीय स्थिति कैसी है?

A देखिए, तमाम वित्तीय चुनौतियों के बीच राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत और स्थिर है। धान में 20 हजार करोड़, महतारी वंदन में 8 हजार करोड़, धान में 12 हजार करोड़ राज्यांश, दो वर्ष के बोनस के रूप में 3700 करोड़ की व्यवस्था, 4 हजार प्रति मानक बोरा की जगह 5500 रुपये तेंदूपत्ते की खरीदी, 7 हजार की जगह अब दीनदयाल भूमिहीन कृषक योजना के तहत प्रदेश के 6 लाख भूमि कृषक मजदूरों को 10 हजार प्रदान करना जैसी नई योजनाओं की नई वित्तीय चुनौतियों का सामना करना है, जबकि पीडीएस, आयुष्मान भारत, पांच एचपी पंपों पर बिजली अनुदान जैसी अनेक योजनाएं पहले से ही संचालित हैं। इन चुनौतियों के बीच 8 हजार करोड़ स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत केंद्र से एक साल में लाना हो, 12 हजार करोड़ अतिरिक्त की राशि पेंशन के अंतर्गत प्राप्त करना हो या कर राजस्व में सुधार की बात हो, इन सब कदमों से वित्तीय प्रबंधन की बड़ी चुनौतियों को हम संभाल पाने में सफल हुए हैं

Q प्रशासनिक सेवा का अनुभव आपके राजनीतिक कार्य में कैसे मदद करता है?

A आईएएस के रूप मिले दायित्वों के अनुभव ने मुझे नीति निर्माण, बजट प्रबंधन और कार्यान्वयन की गहरी समझ दी। यह निर्णय लेने में व्यवस्थित और डेटा-संचालित दृष्टिकोण लाता है, जो राजनीतिक संवेदनशीलता को अधिक प्रभावी बनाता है।

Q एक आईएएस और राजनेता के रूप में निर्णय लेने में सबसे बड़ा अंतर क्या है?

A राजनीति में आने के बाद मेरी निर्णय प्रक्रिया में जनता, समाज के प्रति संवेदनशीलता व दायित्वबोध अधिक बढ़ा है। दोनों अनुभवों का संयोजन मुझे संवेदनशीलता, व्यापक दृष्टिकोण और जनता, समाज, राज्य और राष्ट्र के प्रति सोच प्रदान करता है।

आपातकाल

देश कभी माफ नहीं करेगा कांग्रेस को...

सच्चिदानंद उपासने

25-26 जून 75 की मध्य रात्रि को हमारी पीढ़ी का कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता चाहे वह किसी भी विचारधारा का क्यों ना हो कभी नहीं भूलेगा। यह एक अभूतपूर्व अनुभव था। 1971-72 में गुजरात और बिहार में राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ था ,बहुत ही कम समय में वह आंदोलन नव निर्माण आंदोलन के रूप में पूरे देश में फैल गया।

देश में आजादी के बाद एक कालखंड ऐसा भी आया जब 1975 से 77 के बीच हमारे देश के सत्ता लोभी कर्णधारों ने संविधान को पूरी तरह से कंबल में लपेटकर सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला घोटकर सारी शक्तियां अपने हाथों में लेने के इरादे से उसे अपना सुरक्षा कवच बना डाला। उस घटना को 51 साल होने को हैं। जैसे-जैसे सदियां खत्म हो रही हैं, उस घटना को कई लोग भूल रहे हैं, जबकि कुछ लोग जान बूझकर उसे गुमनामी के परदे के पीछे धकेलने का नेक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वह घटना देश के इतिहास और लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना जरूरी है कि उसे कभी भुलाया ना जाए।

25-26 जून 75 की मध्य रात्रि को हमारी पीढ़ी का कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता चाहे वह किसी भी विचारधारा का क्यों ना हो कभी नहीं भूलेगा। यह एक अभूतपूर्व अनुभव था। 1971-72 में गुजरात और बिहार में राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ था ,बहुत ही कम समय में वह आंदोलन नव निर्माण आंदोलन के रूप में पूरे देश में फैल गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में यह सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बन गया। सत्तारूढ़ कांग्रेस के भ्रष्ट शासन के खिलाफ जनता का असंतोष चरम पर पहुंच गया था। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी। इसके कारण देश में जो राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई, वह कल्पना से परे थी। कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि देश का राजनीतिक माहौल क्या करवट लेगा? ऐसे माहौल में 25 जून 1975 की मध्य रात्रि को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से आपातकाल लगाने की घोषणा की। "देश में आंतरिक शत्रुओं द्वारा अस्थिरता पैदा करने के कारण देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है, इसलिए राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए आपातकाल की घोषणा की है।" उन्होंने यह विषय वस्तु बताते हुए घोषणा की। ऑल इंडिया रेडियो पर उनके बयान के प्रसारित होने से पहले ही देश भर में पुलिस बल बहुत सक्रिय हो गया था। विपक्ष के सभी बड़े-छोटे नेताओं के घरों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई थी। यह सुरक्षा व्यवस्था जिलों के शहरों तक फैली हुई थी। कुछ अभूतपूर्व और भयानक घटने वाला था। सतर्क और जानकार नागरिकों को इसका आभास था। लेकिन कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि वास्तव में क्या होने वाला है। लेकिन हां, अनिश्चितता और भ्रम ज्यादा देर तक नहीं रहा। श्रीमती इंदिरा गांधी के ऑल इंडिया रेडियो पर दिए गए बयान के तुरंत बाद हर जगह राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी शुरू हो गई। कुछ ही घंटे में लाखों राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। प्रेस पर शिकंजा कसा गया। सभी तरह के संचार बंद कर दिए गए। सिर्फ 48 घंटे में, पूरा देश जेल में तब्दील हो गया और आजाद भारत के इतिहास में एक काला अध्याय शुरू हो गया।

उन सभी घटनाओं को 51 वर्ष बीत गए हैं। इसलिए नई पीढ़ी को उन काले दिनों और उस दौरान किए गए कुकृत्यों के बारे में बताना जरूरी है। क्योंकि जिस मानसिकता से आपातकाल लगाया गया था और देश में राजनीतिक दमन फैलाया गया था, वह पूर्ण अधिनायकवाद की मानसिकता कांग्रेस में समाप्त नहीं हुई है, फिर से मजबूत होने लगी है। जिस फासीवादी विचारधारा वाले लोगों ने श्रीमती इंदिरा गांधी को घेर रखा था और उन्हें गुमराह किया था और उनकी आड़ में अपनी लोकतंत्र विरोधी राजनीति को अंजाम दिया था, वही विचारधारा वाले लोग आज की कांग्रेस पर काबिज हो गए हैं। इसलिए ध्यान में रखना चाहिए कि 51 वर्ष पहले जो लोकतंत्र पर खतरा था वह निकट भविष्य में भी हो सकता है।

आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने राजनीतिक

दमन के जरिए विरोधियों को खत्म करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने सरकारी मशीनरी का मनमाने तरीके से दुरुपयोग किया। हजारों लोग मारे गए ,हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। कई संस्थाएं ध्वस्त हो गईं, जो फिर कभी नहीं खड़ी हो पाई। लेकिन इन सबसे परे उन्होंने भारतीय न्यायपालिका और संसद पर भी अपना राक्षसी दमन चलाया। इन सर्वोच्च संस्थाओं को अपना बनाने के लिए भारत के संविधान के साथ क्रूरता कर उसे समाप्त किया। यह कृत्य तो और भी विनाशकारी था। देश के हर नागरिक को कांग्रेस के इस विनाशकारी विचार से सावधान रहना चाहिए। **संविधान में 38 वां संशोधन – –22 जुलाई –1 अगस्त 1975––** आपातकाल की घोषणा के समय से ही इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने हरसंभव तरीके से संविधान को नष्ट करना शुरू कर दिया था। जिस तरह से राष्ट्रपति के नाम से अधिसूचना जारी की गई थी। देश में तुरंत आपातकाल लागू कर दिया गया। 25 जून 75 तक हमारे संविधान में इस तरह के घरेलू आपातकाल घोषित करने का प्रावधान नहीं था। उस दिन घोषित आपातकाल पूरी तरह से असंवैधानिक था। यह दिखाने के लिए कि उनके जल्दबाजी में लिए गए फैसले में संवैधानिकता थी, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू होने के 28 दिन बाद 22 जुलाई 75 को यह संविधान संशोधन किया। यह संविधान संशोधन पूर्व व्यापी प्रभाव से लागू किया गया। इस तरह का पूर्व व्यापी प्रभाव से लागू करना भी पूरी तरह से असंवैधानिक, अवैध, अनैतिक था।

इस संशोधन ने न्यायपालिका की कई शक्तियां छीन लीं। केंद्र सरकार के सभी कार्यों और निर्णयों को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया और केंद्र सरकार को न्यायपालिका से पूरी सुरक्षा प्रदान की गई। इस संशोधन में संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों और विशेषाधिकारों को वापस लेने या निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति यानी केंद्र सरकार को दे दी। इतना ही नहीं ,राष्ट्रपति को देश के विभिन्न राज्य सरकारों को निर्देशित करने की शक्ति भी दी गई। संक्षेप में, राज्य सरकारों की भी स्वतंत्रता भी छीन ली गई।

इस 38 वें संशोधन में इस तरह से उत्पीड़न के लिए अनुकूल संसाधनों की एक लंबी श्रृंखला शुरू की और 42वें संशोधन ने इसकी परिणिति की।

मूल संविधान सभा ने हमारे संविधान को तैयार करने के लिए करीब 3 साल काम किया था। उस समिति में 389 सदस्य थे। डॉ बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने 114 दिनों तक काम किया था। लेकिन, इंदिरा गांधी ने "अनुभव के आधार पर संविधान में क्या संशोधन किए जाने चाहिए" यह तय करने के लिए केवल एक सदस्य की समिति नियुक्त की और समिति में सिर्फ डेढ़ महीने में अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के आधार पर इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने ऐसे व्यापक बदलाव करने का बीड़ा उठाया। ये बदलाव ऐसे बदलाव थे जो भारतीय संविधान के मूल स्वरूप को पूरी तरह से बदल देते। इन बदलावों से राज्यों की शक्तियां बहुत कम हो जातीं और इस तरह संविधान द्वारा अपनाये गए संघीय सिद्धांत को त्याग दिया गया तथा सारी शक्ति केंद्रीय सरकार के हाथों में केंद्रित कर दी गई।

इस संविधान संशोधन की मदद से 1975 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव स्थगित कर दिए गए और विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया। इसमें यह प्रावधान था कि अगर राष्ट्रपति को जरूरी लगे तो इस स्थगन को और आगे बढ़ाया जा सकता है।

संविधान के 38 वें संशोधन ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनने का काम किया था। लेकिन जब वह पर्याप्त नहीं था, तो 42 वें संशोधन के जरिए सरकार को नागरिकों के जीवन के अधिकारों को छीनने का अधिकार दे दिया गया। लोगों से हर तरह के आचार, विचार, प्रचार की आजादी और विरोध करने का अधिकार भी छीन लिया गया। प्रेस की आजादी पर भी हमला किया गया। यह नियम जड़ जमा चुके थे कि छापने वाली हर लाइन सरकारी जांच एजेंसी के मंजूरी के बाद ही छपनी चाहिए। इस संशोधन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि न्यायपालिका सरकार के निर्देशों अनुसार काम करेगी।

यह संशोधन संविधान की प्रस्तावना में संशोधन का एक अजीबोगरीब काम था, जो दुनिया में कहीं और नहीं किया गया। संविधान सभा ने बहुत व्यापक चर्चा के बाद संविधान में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष शब्दों को शामिल करने से इनकार कर दिया था। पंडित नेहरू से लेकर डा अंबेडकर तक सभी ने यहीं रुख अपनाया था। लेकिन इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने संविधान सभा के उस मूल रूप को पलट दिया और बिना किसी चर्चा के संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता शब्द डाल दिये।

जब इंदिरा गांधी और कांग्रेस इतने बड़े संशोधन कर रही थी और संविधान के मुख्य ढांचे को पूरी तरह से बदल रही थी तब संसद में विपक्ष की बेंच पर कोई नहीं था। क्योंकि वह सभी जेल में थे। स्टालिन और माओ की विचारधारा की दिशा में उनके तरीकों का इस्तेमाल करके जाने का अब तक का सबसे बड़ा प्रयास था।

देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य कई विपक्षी दल तथा छात्र संगठन आपातकाल के विरुद्ध कड़ा संघर्ष कर रहे थे। बेशक, कम्युनिस्ट इंदिरा गांधी के साथ थे, महाराष्ट्र में शिवसेना आपातकाल का समर्थन कर रही थी। सरकारी मशीनरी और कांग्रेस संगठन द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से जनता में असंतोष बढ़ रहा था। उस आंदोलन के दबाव के कारण इंदिरा गांधी को चुनाव कराना पड़ा। उसमें उनकी बुरी तरह से हार हुई। जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, जिसमें तत्कालीन भारतीय जनसंघ भी शामिल था। उस जनता सरकार ने 43 वें और 44 वें संशोधन करके कांग्रेस द्वारा संविधान को पहुंचाई गई क्षति की पूरी तरह से मरम्मत की तथा मूल ढांचे को काफी हद तक पुनर्स्थापित किया। ●●●

लेखक मीसाबंदी और लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं

बाबा नागार्जुन ने यह कविता
आपातकाल के प्रतिवाद में लिखी थी

ख़ूब तनी हो, ख़ूब अड़ी हो, ख़ूब लड़ी हो
प्रजातंत्र को कौन पूछता, तुम्हीं बड़ी हो

डर के मारे न्यायपालिका काँप गई है
वो बेचारी अगली गति-विधि भाँप गई है
देश बड़ा है, लोकतंत्र है सिक्का खोटा
तुम्हीं बड़ी हो, संविधान है तुम से छोटा

तुम से छोटा राष्ट्र हिन्द का, तुम्हीं बड़ी हो
खूब तनी हो,खूब अड़ी हो,खूब लड़ी हो

गांधी-नेहरू तुम से दोनों हुए उजागर
तुम्हें चाहते सारी दुनिया के नटनागर
रूस तुम्हें ताकत देगा, अमरीका पैसा
तुम्हें पता है, किससे सौदा होगा कैसा

ब्रेझनेव के सिवा तुम्हारा नहीं सहारा
कौन सहेगा धौंस तुम्हारी, मान तुम्हारा
हल्दी. धनिया, मिर्च, प्याज सब तो लेती हो
याद करो औरों को तुम क्या-क्या देती हो
मौज, मज़ा, तिकड़म, खुदगर्जी, डाह, शरारत
बेईमानी, दगा, झूठ की चली तिजारत
मलका हो तुम ठगों-उचक्कों के गिरोह में
जिद्दी हो, बस, डूबी हो आकण्ठ मोह में

यह कमजोरी ही तुमको अब ले डूबेगी
आज नहीं तो कल सारी जनता ऊबेगी
लाभ-लोभ की पुतली हो, छलिया माई हो
मस्तानों की माँ हो, गुण्डों की धाई हो

सुदृढ़ प्रशासन का मतलब है प्रबल पिटाई
सुदृढ़ प्रशासन का मतलब है 'इन्द्रा' माई
बन्दूकें ही हुईं आज माध्यम शासन का
गोली ही पर्याय बन गई है राशन का

शिक्षा केन्द्र बनेंगे अब तो फौजी अड्डे
हुकुम चलाएँगे ताशों के तीन तिगड्डे
बेगम होगी, इर्द-गिर्द बस गूल्लू होंगे
मोर न होगा, हंस न होगा, उल्लू होंगे

साभार प्रस्तुति

भारत की नई कृषि यात्रा: फसल से आगे, समृद्धि की ओर

शिवराज सिंह चौहान

आज भारत खाद्यान्न उत्पादन में 3765.63 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर है, जो देश के इतिहास में सबसे ज्यादा है। धान, गेहूं, मक्का, दालें और तिलहन- सभी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। यह केवल ज्यादा पैदावार नहीं, बल्कि कुल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आए विस्तार और मजबूती का प्रमाण है। साथ-साथ, मोदी सरकार ने किसान की जोखिम सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 22 किस्तों के माध्यम से किसानों के खातों में सीधे 4.27 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता पहुंच चुकी है, जिससे 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को हर साल नियमित आय-समर्थन मिलता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में कृषि एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। पहले हमारी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि देश में अनाज की कमी न हो, किसी तरह भूख से बचाव हो जाए। आज प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता और किसान हितैषी नीतियों ने कृषि को सिर्फ 'उत्पादन का क्षेत्र' नहीं रहने दिया, बल्कि किसान की समृद्धि, जोखिम-सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, हरित तकनीक और ग्रामीण विकास का समन्वित आधार बना दिया है। हरित क्रांति के बाद पहली बार नीतियों का फोकस केवल 'कितना उत्पादन' पर नहीं, बल्कि 'किसान की वास्तविक आय कितनी, खेती कितनी टिकाऊ और 'ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत' पर आ गया है। इसी सोच से दलहन-तिलहन मिशन, कॉटन मिशन, प्राकृतिक खेती मिशन, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, खेत बचाओ अभियान, डिजिटल कृषि और शोध-नवाचार; सबको एक ही व्यापक दृष्टि से जोड़ा जा रहा है।

आज भारत खाद्यान्न उत्पादन में 3765.63 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर है, जो देश के इतिहास में सबसे ज्यादा है। धान, गेहूं, मक्का, दालें और तिलहन- सभी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। यह केवल ज्यादा पैदावार नहीं, बल्कि कुल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आए विस्तार और मजबूती का प्रमाण है। साथ-साथ, मोदी सरकार ने किसान की जोखिम सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 22 किस्तों के माध्यम से किसानों के खातों में सीधे 4.27 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता पहुंच चुकी है, जिससे 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को हर साल नियमित आय-समर्थन मिलता है। लंबे समय तक दालें, खाद्य तेल और कपास तीनों क्षेत्र हमारी पूरी क्षमता से पीछे रहे। हम दालों और तेलों के लिए आयात पर निर्भर रहे और कपास में भी किसानों को वैश्विक उत्तार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा। मोदी सरकार ने इन तीनों को रणनीतिक प्राथमिकता देते हुए अलग-अलग मिशन के रूप में आगे बढ़ाया है। राष्ट्रीय दलहन मिशन के माध्यम से तुअर, उड़द, मसूर, चना और अन्य दालों का क्षेत्र और उत्पादकता बढ़ाने के लिए बीज से लेकर बाजार तक पूरी वैल्यू चेन पर काम हो रहा है- उच्च-उपज किस्में, क्लस्टर आधारित खेती, प्रसंस्करण इकाइयां, एमएसपी का सुदृढ़ ढांचा, सरकारी खरीद, भंडारण और निर्यात तक। प्राकृतिक खेती को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारा संकल्प है कि 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए सेंसिटाइज किया जाए, उनमें से लगभग 18 लाख किसानों को सक्रिय रूप से प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए तैयार किया जाए और चरणबद्ध रूप से करीब 75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के दायरे में लाया जाए। भारत जैसे विशाल देश में कुछ क्षेत्र बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ जिले अलग-अलग वजहों से पीछे रह जाते हैं। इस असमानता को कम करने के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की संकल्पना की गई है। इस योजना के तहत लगभग 100 कम उत्पादन वाले जिलों की पहचान की गई है, जहां प्रति हेक्टेयर पैदावार राष्ट्रीय औसत से काफी कम है और किसान अपेक्षित लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इन जिलों में ।। विभागों की 36 योजनाओं का कन्वर्जेन्स कर एक समग्र पैकेज दिया जा रहा है- सिंचाई, मृदा स्वास्थ्य, बीज, उर्वरक, फसल विविधीकरण, पशुपालन, बागवानी, कृषि-उपकरण, कौशल विकास, अवसंरचना और बाजार-जुड़ाव; सबको एक साथ जोड़कर। उत्पादन बढ़ाने की दौड़ में कई जगहों पर मिट्टी और पानी पर दबाव बढ़ा है। असंतुलित उर्वरक उपयोग, भूजल का अत्यधिक दोहन और सीमित फसल चक्र ने खेत की सेहत को प्रभावित किया है। यदि समय रहते दिशा न बदली जाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कमजोर खेत और थकी हुई मिट्टी छोड़ेंगे। इस चुनौती को देखते हुए 'खेत बचाओ अभियान' शुरू किया गया है। ।•••

मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना

राहत, विश्वास और वित्तीय संतुलन की पहल : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 छत्तीसगढ़ सरकार की उन महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी पहलों में शामिल है, जिनका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और बकाया बिजली बिलों के बोझ से दबे उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा शुरू की गई यह योजना केवल बकाया राशि के निपटारे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य में उपभोक्ता हितों को केंद्र में रखकर ऊर्जा क्षेत्र में विश्वास बहाली और वित्तीय संतुलन स्थापित करने का एक व्यापक प्रयास है।

कोरोना महामारी ने देशभर की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ आम नागरिकों की आजीविका पर भी गहरा प्रभाव डाला। छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं रहा। लॉकडाउन, रोजगार में कमी और आय के सीमित स्रोतों के कारण बड़ी संख्या में लोग अपने नियमित खर्चों का प्रबंधन करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। इसी दौरान संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कई महीनों तक बिजली मीटरों की नियमित रीडिंग भी प्रभावित हुई। परिणामस्वरूप अनेक उपभोक्ताओं को एक साथ कई महीनों के बिजली बिल प्राप्त हुए, जिनका भुगतान करना उनके लिए संभव नहीं हो पाया।

समय बीतने के साथ बकाया राशि पर अधिभार जुड़ता गया और लाखों उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ता चला गया। इस स्थिति ने न केवल उपभोक्ताओं को परेशान किया, बल्कि बिजली वितरण व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला। बढ़ती बकाया राशि से वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति प्रभावित होने लगी। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 की शुरुआत की है।

इस योजना के तहत प्रदेश के 29 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को लगभग 758 करोड़ रुपये तक की सीधी राहत प्रदान की जाएगी। बिजली क्षेत्र में इतनी बड़ी राशि की छूट पहली बार दी जा रही है। योजना का उद्देश्य उन उपभोक्ताओं को राहत देना है, जो आर्थिक कारणों से अपने बकाया बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर पाए हैं और नियमित उपभोक्ता की श्रेणी में वापस आना चाहते हैं।

योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2023 की स्थिति में बकाया राशि को आधार मानकर लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसमें निम्नदाब घरेलू, बीपीएल और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है। पात्र उपभोक्ताओं को मूल राशि और अधिभार (सरचार्ज) में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार छूट दी जा रही

है। यह व्यवस्था उपभोक्ताओं को बकाया राशि के बोझ से बाहर निकलने और सरल तरीके से अपने बिजली खातों को नियमित करने का अवसर प्रदान करती है।

राज्य स्तरीय रिपोर्ट के अनुसार योजना को उपभोक्ताओं का व्यापक समर्थन मिल रहा है। अब तक कुल 7 लाख 96 हजार 961 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें 6 लाख 9 हजार 289 आवेदन बीपीएल श्रेणी के हैं, जबकि 1 लाख 54 हजार 281 आवेदन एपीएल श्रेणी और 33 हजार 394 आवेदन कृषि उपभोक्ताओं से प्राप्त हुए हैं। अब तक 6 लाख 38 हजार 335 आवेदनों को स्वीकृति दी जा चुकी है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि योजना का लाभ समाज के उस वर्ग तक सबसे अधिक पहुंच रहा है, जिसे इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है।

आंकड़ों का विश्लेषण यह भी बताता है कि कुल आवेदनों में बीपीएल उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी लगभग 76 प्रतिशत है। यह दर्शाता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर बिजली बिलों का दबाव अधिक रहा है और समाधान योजना उनके लिए वास्तविक राहत का माध्यम बन रही है। वहीं बड़ी संख्या में स्वीकृत आवेदनों से यह स्पष्ट होता है कि योजना के क्रियान्वयन में प्रशासनिक स्तर पर तेजी और पारदर्शिता बरती जा रही है।

इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इससे केवल उपभोक्ताओं को ही लाभ नहीं होगा, बल्कि बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी। लंबे समय से लंबित बकाया राशि की वसूली होने से वितरण कंपनियों के राजस्व में वृद्धि होगी, जिससे वे बिजली अधोसंरचना के विकास, रखरखाव और उपभोक्ता सेवाओं के विस्तार पर अधिक निवेश कर सकेंगी। इस प्रकार यह योजना उपभोक्ताओं और बिजली कंपनियों, दोनों के हितों के बीच संतुलन स्थापित करती है।

योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को 30 जून 2026 तक पंजीयन कराना होगा। पंजीयन की सुविधा मोर बिजली ऐप, सभी विद्युत वितरण केंद्रों, कार्यालयों और विशेष शिविरों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा गांव-गांव में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों के उपभोक्ता भी आसानी से योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि समाधान योजना के अंतर्गत बकाया राशि का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (एम-ऊर्जा) का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके तहत 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक आधी बिल राशि की छूट प्रदान की जाएगी। इससे स्पष्ट है कि यह योजना केवल पुराने बकाया के समाधान तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में भी उपभोक्ताओं को निरंतर राहत प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

540 करोड़ से अधिक की राहत लाखों उपभोक्ताओं को लाभ

मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 के प्रारंभिक आंकड़े यह संकेत देते हैं कि यह पहल केवल बकाया राशि की वसूली तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में उपभोक्ता विश्वास और वित्तीय संतुलन स्थापित करने की दिशा में प्रभावी साबित हो रही है। 18 जून 2026 तक राज्य में सक्रिय विद्युत कनेक्शनों के अंतर्गत 7 लाख 92 हजार 310 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 6 लाख 35 हजार 407 आवेदनों को स्वीकृति मिल चुकी है। उल्लेखनीय है कि कुल आवेदनों में लगभग 77 प्रतिशत हिस्सेदारी बीपीएल उपभोक्ताओं की है जो यह दर्शाती है कि योजना का लाभ मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक पहुंच रहा है। योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी लचीली भुगतान व्यवस्था है। एकमुश्त भुगतान के साथ-साथ तीन, छह और छह से अधिक किस्तों का विकल्प उपभोक्ताओं को उनकी आर्थिक क्षमता के अनुरूप भुगतान करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। आंकड़ों के अनुसार, बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने लंबी अवधि वाली किस्तों को अपनाया है, जिससे स्पष्ट है कि आसान भुगतान विकल्प योजना की सफलता का प्रमुख आधार बन रहे हैं। अब तक 2 लाख 51 हजार 631 उपभोक्ताओं के मामलों का निराकरण किया जा चुका है, जिनसे 75 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली हुई है। वहीं उपभोक्ताओं को कुल 540 करोड़ रुपये से अधिक की राहत दी गई है, जिसमें अधिभार छूट का हिस्सा सबसे अधिक है। इसके अतिरिक्त, निष्क्रिय विद्युत कनेक्शनों के लिए भी 164 करोड़ रुपये से अधिक की छूट स्वीकृत की गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि समाधान योजना उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देने के साथ-साथ बिजली वितरण कंपनियों की राजस्व स्थिति को सुदृढ़ करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

राष्ट्र-आराधना और सेवा के अमर साधक श्रद्धेय सिन्हा जी

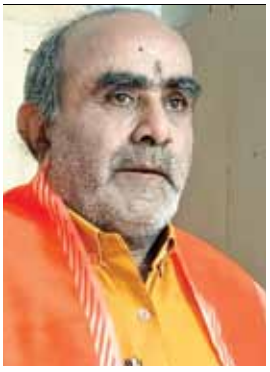

अनिल पुरोहित

श्रद्धेय स्व. सिन्हा जी से मेरा प्रत्यक्ष परिचय सन् 1978 में हुआ था। तब लगभग 20 वर्ष की आयु में वे बागबाहरा (जिला- महासमुन्द) में 15 अगस्त से प्रारम्भ हुए सरस्वती शिशु मन्दिर के प्रथम आचार्य के तौर पर नियुक्त होकर आए थे। यह विद्यालय तब अविभाजित रायपुर जिले का प्रथम और अविभाजित मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ अंचल का दूसरा विद्यालय था।

छत्तीसगढ़ की पावन धरा ने ऐसे कई मनीषियों और कर्मयोगियों को जन्म दिया है जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन समाज के पुनर्निर्माण और राष्ट्र-सेवा में समर्पित कर दिया। इन्हीं तपस्वियों में एक मूर्धन्य नाम है- श्रद्धेय स्व. रूपनारायण सिन्हा जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक, भारतीय जनता पार्टी के कुशल संगठक और छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में उनका जीवन समाज के हर वर्ग के लिए एक जीवन्त प्रेरणापुंज है।

श्रद्धेय स्व. सिन्हा जी से मेरा प्रत्यक्ष परिचय सन् 1978 में हुआ था। तब लगभग 20 वर्ष की आयु में वे बागबाहरा (जिला- महासमुन्द) में 15 अगस्त से प्रारम्भ हुए सरस्वती शिशु मन्दिर के प्रथम आचार्य के तौर पर नियुक्त होकर आए थे। यह विद्यालय तब अविभाजित रायपुर जिले का प्रथम और अविभाजित मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ अंचल का दूसरा विद्यालय था। छत्तीसगढ़ में सरस्वती शिशु मन्दिर का पहला विद्यालय सरगुजा सम्भाग के मुख्यालय अम्बिकापुर में प्रारम्भ हुआ था। श्रद्धेय स्व. सिन्हाजी के साथ तब प्रधानाचार्य के तौर पर श्री रामाश्रय सिंह, आचार्य श्री अयोध्या प्रसाद साहू व दीदीजी (आचार्या) बदरादेवी शर्मा भी इस विद्यालय में सेवारत थीं। तब मैं हायर सेकेण्डरी का विद्यार्थी था। संघ के वैचारिक अधिष्ठान से अपने पूज्य पिताजी श्रद्धेय स्व. देवकृष्ण जी पुरोहित (जो इस विद्यालय और उसे संचालित करने वाली संचालन समिति के संस्थापक थे) के मार्गदर्शन में जुड़े रहने के कारण मेरा सहज लगाव तभी से इस विद्यालय से बना रहा। इसी दौरान श्रद्धेय स्व. सिन्हा जी से प्रगाढ़ सम्बन्धों का धरातल सिंचित हुआ और इसकी शीतलता ने सदैव मुझे सुखद अनुभूतियों से सराबोर रखा। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी स्व. सिन्हाजी का सम्पूर्ण जीवन साधना, सादगी और संकल्प की एक ऐसी त्रिवेणी था, जिसने छत्तीसगढ़ के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य पर अपनी अमिट छाप छोड़ी।

संघ साधनाः ध्येय मार्ग पर अनवरत बढ़ते कदम

श्रद्धेय स्व. सिन्हा जी के व्यक्तित्व की नींव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में पड़ी। रायपुर महानगर, रायपुर विभाग व बिलासपुर विभाग में एक प्रचारक के रूप में उन्होंने अपना घर-परिवार छोड़कर राष्ट्र को ही अपना परिवार मान लिया। बाद में उन्होंने विवाह किया लेकिन संघ के वरिष्ठ प्रचारक के रूप में उनका जीवन गृहस्थ प्रचारक के रूप में राष्ट्र-प्रथम की भावना से ओतप्रोत था। उन्होंने उस दौर में संघ कार्य का विस्तार किया, जब साधन बेहद सीमित थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी— प्रत्येक स्वयंसेवक से आत्मीय सम्बन्ध बनाना। वे संगठन के कार्यकर्ता नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य गढ़ते थे। उनकी सादगी और निश्छल मुस्कान कठिन-से-कठिन मोर्चे पर भी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा फूँक देती थी। इसका एक उदाहरण बागबाहरा की शाखा में प्रस्तुत किया और (सम्भवतः सन् 1981 में) उन्होंने बागबाहरा में संघ के विजयादशमी उत्सव पर घोष के साथ संघ का भव्य पथ-संचलन निकालने के विचार को तब साकार किया, जब बागबाहरा में हम जैसे विद्यार्थी स्वयंसेवक इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते थे। वह कार्यक्रम काफी प्रभावोत्पादक रहा और आज भी उस कार्यक्रम की याद बागबाहरा के मानस-पटल पर अंकित है।

बस्तर व बिलासपुर में संगठन शिल्पी की भूमिका

जब संगठन ने उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक सुदृढ़ीकरण की जिम्मेदारी सौंपी, तब श्रद्धेय स्व. सिन्हा जी ने बस्तर और बिलासपुर सम्भाग के संगठन मंत्री के रूप में अपने दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। बस्तर जैसे दुर्गम, संवेदनशील और भौगोलिक रूप से कठिन क्षेत्र में उन्होंने अथक प्रवास किए। आदिवासियों और समाज के अन्तिम छोर पर बैठे व्यक्ति के बीच जाकर उन्होंने राष्ट्रवाद का बीज बोया। इसी प्रकार बिलासपुर सम्भाग में उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन को खड़ा करने में एक कुशल शिल्पी की भूमिका निभाई। वे केवल एक नेता या पदाधिकारी नहीं थे, बल्कि कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक और अभिभावक थे। सत्ता और पद की चकाचौंध से दूर, उन्होंने हमेशा 'वैचारिक शुद्धता' और 'अन्त्योदय' के सिद्धान्तों को सर्वोपरि रखा।

छत्तीसगढ़ योग आयोग में स्वास्थ्य और संस्कृति का समन्वय

छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में श्रद्धेय स्व. सिन्हा जी ने योग को जन-आंदोलन का रूप दिया। उनका मानना था कि योग केवल शारीरिक कसरत नहीं, बल्कि आत्मा और मन को शुद्ध करने की सनातन विधा है। 'स्वस्थ नागरिक ही एक समर्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है' —इस ध्येय वाक्य को उन्होंने अपने कार्यों से चरितार्थ किया। उनके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के सुदूर गाँवों से लेकर शहरों तक योग शिविरों का जाल बिछाया गया और नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति, प्राणायाम और योग विज्ञान से जोड़ने के लिए भगीरथ प्रयास किए गए। शासकीय स्तर पर योग को जो गरिमा और विस्तार उनके नेतृत्व में मिला, वह सदैव याद रखा जाएगा।

सादगी और शुचिता के प्रतीक : स्मृतियों में सदैव जीवन्त

श्रद्धेय स्व. सिन्हा जी का कर्तृत्व जितना विशाल था, उनका व्यक्तित्व उतना ही सरल और सहज था। उच्च पदों पर रहने के बावजूद उनके भीतर का 'अहं' कभी जागृत नहीं हुआ। साधारण जीवन-शैली, मृदुभाषी स्वभाव और हर किसी की मदद के लिए तत्पर रहना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। वे विपरीत विचारधारा के लोगों के बीच भी अपने तर्कों, शुचिता और व्यवहार कुशलता के कारण अत्यन्त आदरणीय थे। श्रद्धेय स्व. सिन्हा जी आज भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका कर्तृत्व, उनके द्वारा गढ़े गए हजारों कार्यकर्ता और उनके विचार छत्तीसगढ़ की माटी में सुगन्ध बनकर रचे-बसे हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि पद आते-जाते रहते हैं, लेकिन जो कार्य निःस्वार्थ भाव से समाज के लिए किया जाता है, वही अमर रहता है। बस्तर के जंगलों से लेकर बिलासपुर के मैदानों तक और संघ की शाखाओं से लेकर योग आयोग के मंचों तक, उनकी स्मृतियाँ सदैव राष्ट्र-आराधना के मार्ग को आलोकित करती रहेंगी। ऐसे महान राष्ट्र-साधक और छत्तीसगढ़ के गौरव श्रद्धेय स्व. सिन्हा जी की पावन स्मृतियों को कोटि-कोटि नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि!! |•••

उनका सेवाभावी व्यक्तित्व सदैव स्मरणीय रहेगा : साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव ने कहा कि संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक, भाजपा के पूर्व संगठन मंत्री एवं छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रहे रूपनारायण सिन्हा का नहीं रहना मेरे लिए किसी बड़े नुकसान से कम नहीं है। उनका निधन भाजपा परिवार, संगठन और प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है।

कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व के धनी थे : किरण देव

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्याक्ष रूपनारायण सिन्हा के आकस्मिक और दुखद देहावसान घर गहरा शोक व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में उन्होंने रूपनारायण सिन्हा का असमय निधन हम सबके लिए दुखद है। जिसकी भरपाई संभव नहीं है।

रूपनारायण जी हम सभी के लिए प्रेरणादायी रहेंगे : जाम्वाल

भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल ने छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता रूपनारायण सिन्हा का निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि संगठन के प्रति स्व. सिन्हा का समर्पण सबके लिए सदैव प्रेरणादायी रहेगा।

रूपनारायण जी का हर वर्ग में गहरा सम्मान थाः साय

भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने स्व. रूपनारायण सिन्हा के निधन को भाजपा परिवार के लिए एक बड़ी क्षति बताया। साय ने कहा कि स्व. सिन्हा सौम्य, सरल और समर्पित व्यक्तित्व के धनी थे। संगठन के कार्यों में उनकी सक्रियता और निष्ठा हमेशा याद रखी जाएगी।

उनका समर्पण व सेवा भाव सदैव प्रेरणा देता रहेगाः साव

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि "रूपनारायण सिन्हा जी का निधन छत्तीसगढ़ के योग, स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने योग के माध्यम से जनकल्याण और स्वस्थ समाज निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका समर्पण, सादगी और सेवा भाव सदैव प्रेरणा देता रहेगा।

सिन्हा जी अनुशासन और समर्पण का प्रतीक थेः शर्मा

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि रूपनारायण सिन्हा जी ने योग को जन-जन तक पहुँचाने और स्वस्थ समाज के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनका जीवन सेवा, अनुशासन और समर्पण का प्रतीक था। उनके निधन से प्रदेश ने एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व को खो दिया है। |•••

जनसेवा, संगठन और समर्पण के पर्याय थे भरत लाल मटियारा जी

उत्तर बस्तर कांकेर जिले के ग्राम ठेलकाबोड़ में 8 मार्च 1964 को जन्मे भरत लाल मटियारा का जीवन संगठन, समाज सेवा और राष्ट्रहित के प्रति समर्पण का प्रेरक उदाहरण है। कृषि को अपना व्यवसाय और जनसेवा को अपना ध्येय मानने वाले श्री मटियारा ने चार दशकों से अधिक समय तक भारतीय जनता पार्टी और सामाजिक संगठनों में सक्रिय भूमिका निभाकर अपनी अलग पहचान बनाई है।

वर्ष 1984 में भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने संगठन के विभिन्न दायित्वों का सफल निर्वहन किया। युवा मोर्चा के शहर अध्यक्ष से लेकर भाजपा कांकेर जिला अध्यक्ष और वर्तमान में प्रदेश कार्यसमिति सदस्य तक का उनका राजनीतिक सफर निरंतर सक्रियता और समर्पण से परिपूर्ण रहा है। उन्होंने अनेक लोकसभा और विधानसभा चुनावों में चुनाव अभिकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें पार्टी प्रत्याशियों को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। श्री मटियारा ने केवल राजनीति तक स्वयं को सीमित नहीं रखा, बल्कि सामाजिक और सामुदायिक संगठनों में भी नेतृत्व प्रदान किया। पिछड़ा वर्ग समाज, धीवर समाज तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के अध्यक्ष और पदाधिकारी के रूप में उन्होंने समाज के वंचित वर्गों की आवाज को मजबूती दी। छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने मत्स्य पालक समुदाय के उत्थान के लिए अनेक प्रयास किए। वर्तमान में भी वे राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रशिक्षित स्वयंसेवक के रूप में श्री मटियारा ने राष्ट्रवादी विचारधारा को समाज के बीच पहुंचाने का कार्य किया है। श्रीराम मंदिर निर्माण समिति, बस्तर संभाग में संगठनात्मक दायित्व तथा विभिन्न जिलों के प्रभारी के रूप में उनकी कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता लगातार प्रमाणित हुई है। सादगी, सहजता और जनसंपर्क उनकी सबसे बड़ी पहचान है। श्री भरत मटियारा जी का निधन 17 मई 2026 को हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ।

भरत लाल मटियारा

8 मार्च 1964/17 मई 2026

उनका समूचा जीवन संगठन को समर्पित रहा है। वे सदैव संगठन के विस्तार के लिए जुटे रहे। समाज में हर वर्ग का उत्थान हो इसके लिए सतत् सक्रिय रहे हैं। पार्टी में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। वे हर कार्यकर्ता के लिए प्रेरणादायी रहेंगे। उनके असमय निधन से हम सबको अपूर्णीय क्षति हुई है।

-महेश जैन, भाजपा जिलाध्यक्ष, कांकेर

संक्षिप्त परिचय

- **जन्म:** 8 मार्च 1964
- **प्रमुख रुचि :** समाज सेवा एवं संगठन कार्य
- **पूर्व पद :** भाजपा कांकेर जिला अध्यक्ष (2010-2016)
- **पूर्व अध्यक्ष :** छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड (2017-2019)
- **वर्तमान दायित्व :** अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड (राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त), प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, भाजपा
- **विशेष पहचान :** संगठन कुशलता, सामाजिक नेतृत्व और बस्तर क्षेत्र में जनसेवा

पत्रिका दीप कमल के वाट्सएप समूह से जुड़ने व ई-पत्रिका प्राप्त करने के लिए कृपया QR कोड स्केन करें।

निवेदन दीप कमल से संबंधित कोई भी सुझाव या शिकायत हो तो आप नीचे दिए गए पते पर भेज सकते हैं। फोन या मोबाइल नंबर पर भी जानकारी दे सकते हैं। ईमेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके क्षेत्र में संगठन से संबंधित कोई गतिविधि या पत्रिका में प्रकाशन योग्य कोई समाचार हो, तो उसे भी निम्नलिखित माध्यमों से भेजने का आग्रह है।

संपादक, दीप कमल, प्रदेश भाजपा कार्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर डूमरतराई, रायपुर। (छग), मोबाइल नंबर : 92016-33511, फोन : 0771-2233500,
Email : mydeepkamal@gmail.com

सेवा, सुशासन और संकल्प के 12 साल

RNI No.CHHHIN/2004/13926

नि:शुल्क विज्ञापन

12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के

स्वास्थ्य को सुरक्षा कवच
2.46 करोड़+ हितग्राहियों
को मिली स्वास्थ्य सुरक्षा

पेयजल हर आंगन
41 लाख+ परिवारों को
मिला नल कनेक्शन

नक्सलमुक्त भारत,
नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़
बस्तर से सशस्त्र माओवाद का अंत

शक्ति का सम्मान
68 लाख+ महिलाओं
को महतारी वंदन
योजना के तहत
सालाना
₹12 हजार की आर्थिक सहायता

वित्तीय समावेशन
1.87 करोड़+ हितग्राहियों
के जन धन खाते खुले

सम्मान की सौगात
24 लाख+ किसानों को
सालाना ₹6,000 की
आर्थिक सहायता

छप्पर की जगह पक्की छत
26 लाख+ परिवारों के
पक्के आवासों की स्वीकृति

धुआं छंटा, मुस्कान खिली
38 लाख+ महिलाओं को
मिला गैस कनेक्शन

मोदी की गारंटी से आगे बढ़ता छत्तीसगढ़

श्री विष्णु देव साय, माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़